RAJHIN/2014/55262

sancharjagat.com

संचार जगत

दैनिक समाचार पत्र

sancharjagat.com | editorial@sancharjagat.com

खबरों व विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
संचार जगत
मो.नम्बरः- +917357161599

'सोच को इतना बड़ा रखो कि असफलता भी एक छोटा कदम लगे। सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक दिशा है। बड़ा सोचो, बड़ा करो।'

वर्षः 13 | अंकः 275 | जयपुर, बुधवार, 04 नवम्बर 2026 | मूल्यः 2.00 रूपए | पृष्ठः 8

अनिश्चितकाल तक किसी तय प्रोटेस्ट साइट पर नहीं बैठ सकते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी को विरोध प्रदर्शन करने का हक, किसी जगह पर कब्जा नहीं कर सकते

नई दिल्ली/संचार जगत



सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी तय जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकता। हालांकि, हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है।

इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों के मौसम में विरोध प्रदर्शन के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने का आरोप लगाने वाली किराना कमेटी दिल्ली की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ये विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किए जा रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन के कारण आसपास के इलाकों में कारोबार प्रभावित हो रहा है और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारी संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि प्रदर्शन स्थल के आसपास करीब 50 लाख लोग रहते हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते दुकानें बंद हैं और त्योहारों के मौसम में व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अदालत से आउट ऑफ द बॉक्स समाधान तलाशने की अपील की। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, आप किसी जगह पर हर समय कब्जा नहीं कर सकते। किसान, पत्रकार और दूसरे लोग कहां जाएंगे? हर किसी को विरोध करने का अधिकार है। इसके लिए एक निश्चित समय और जगह तय की जानी चाहिए।

सीजेपी को एक दिन की अनुमति मिली, 17 दिन तक बैठे रहे

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की ओर से कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए सिर्फ एक दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी 17 दिन तक वहां बैठे रहे। मेहता ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति संसद की ओर मार्च भी किया। संसद देश की संप्रभुता का प्रतीक है। बिना अनुमति संसद या सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जो संगठन बंद या प्रदर्शन का आह्वान करता है, उसे उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। सुनवाई में सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने करीब 7 हजार लोगों को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोकतंत्र के रूप में हम इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि इन लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया था, बल्कि प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली कानून व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय बैठक

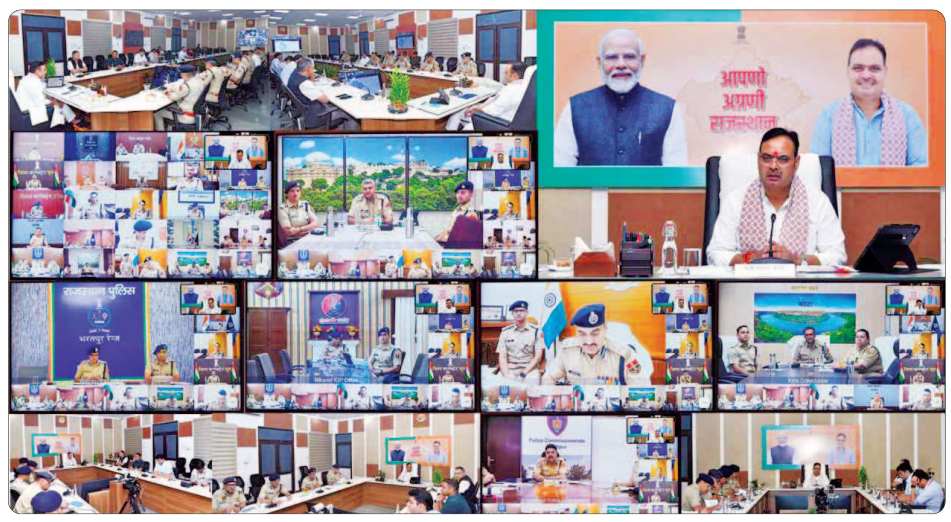
फील्ड में उतरें वरिष्ठ अधिकारी, किसी भी घटना पर तुरंत लें संज्ञान : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

त्योहारी सीजन में हों सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम, यातायात और अग्निशमन की हो पुख्ता व्यवस्था

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर बाजारों, सार्वजनिक स्थलों एवं पर्यटन केन्द्रों पर आवाजाही बढ़ जाती है। त्योहारी सीजन में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लें और सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करें।

पैदल गश्त, रात्रिकालीन पेट्रोलिंग और नाकाबंदी बढ़ाएं

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कानून व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस की नियमित मौजूदगी बनाए रखने के साथ ही पैदल गश्त, रात्रिकालीन पेट्रोलिंग और प्रभावी नाकाबंदी पर विशेष ध्यान दिया जाए।



'नशा तस्करों के नेटवर्क को करें ध्वस्त'

मुख्यमंत्री ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को निरंतर प्रभावी बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारी सीजन में पुलिस की व्यस्तता का फायदा ड्रग माफिया उठा सकते हैं। ऐसे में नशा तस्करी और तस्करों पर विशेष निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया एवं सक्रिय तस्करों को चिह्नित कर उनके नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार करने के निर्देश दिए।

दो कदम आगे रहकर सायबर अपराधियों पर कसें नकेल

मुख्यमंत्री ने दीपावली के दौरान बढ़ने वाले सायबर अपराधों को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सायबर टीम को 24 घंटे सक्रिय रखा जाए तथा सायबर अपराधों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि दो कदम आगे रहकर सायबर अपराधियों की गतिविधियों एवं उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाकर उन्हें चिह्नित किया जाए, ताकि समय रहते सायबर धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके।

सोशल मीडिया पर रखें पैनी नजर

उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर विशेष सतर्कता बरती जाए। वहीं, सोशल मीडिया पर अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं एवं भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों पर प्रभावी निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस टीम को सोशल मीडिया विशेषज्ञों को साथ लेकर काम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले सीएलजी सदस्यों, सीएलजी यूथ और सुरक्षा सखियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं। **पटाखों की अवैध बिक्री रोकें, अग्निशमन व्यवस्थाएं हों पूर्ण;** उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानों पर सुरक्षा मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। अवैध रूप से पटाखों की बिक्री और भंडारण पर विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही, पटाखों की दुकानों वाले इलाकों में संभावित आगजनी की घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन व्यवस्थाएं पूरी तरह मुस्तैद रखी जाएं।

सीईओ को निर्देश

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कटा है तो फार्म-6 भरें

नई दिल्ली/संचार जगत

चुनाव आयोग ने पहली बार वोटर बनने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म-6 में एक घोषणा को लेकर पुराने वोटरों में चल रहे डर के माहौल को खत्म करते हुए कहा है कि अगर उनका नाम एसआईआर के तहत जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है। तो वह इसके लिए वोटर लिस्ट में फिर से अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं।

इसके लिए दी जाने वाली घोषणा झूठी नहीं मानी जाएगी

फॉर्म में इस तरह की घोषणा करनी पड़ती है। जिसमें मैं घोषणा करता/करती हूं कि मतदाता सूची में मेरा नाम पहली बार शामिल करने के लिए यह आवेदन है। इस तरह की घोषणा करने से पुराने वोटर बच रहे हैं। पुराने मतदाताओं को लग रहा है कि अगर वे यह घोषणा देंगे तो यह झूठा शपथ पत्र होगा। क्योंकि वे पहले से वोटर हैं। जो की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत झूठी घोषणा पर सजा और अभियोजन का प्रावधान करती है। इसी डर से लोग फॉर्म-6 भरने से हिचकिचा रहे हैं। इस मामले को स्पष्ट करते हुए आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ को भी यह निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी पुराने वोटर का नाम नहीं आया है और वह वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। तो इसके लिए वह फॉर्म-6 भर सकते हैं। जिसमें की गई घोषणा को झूठा नहीं माना जाएगा।

होंडा पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करने की तैयारी में जुटी

नई दिल्ली/संचार जगत



वाहन विनिर्माता होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि वह अगले महीने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) पेश करेगी। भविष्य में भारत इस मॉडल के लिए उसका वैश्विक उत्पादन केंद्र भी होगा।

कंपनी ने बयान में कहा कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का वैश्विक अनावरण दो दिसंबर को भारत में किया जाएगा। इस मॉडल का नाम 'होंडा अल्फा' रखा गया है। होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तोशियुकी यानागिसावा ने कहा, /"भविष्य में भारत इस मॉडल का वैश्विक उत्पादन केंद्र होगा। यह होंडा के इलेक्ट्रिक सफर में एक अहम कदम है और भारतीय बाजार के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।/"

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को पहली बार 2025 में जापान मोबिलिटी शो में कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया था। कंपनी ने बताया कि 'होंडा अल्फा' भारत में उसका पहला मॉडल होगा, जिस पर हाल में वैश्विक स्तर पर पेश किया गया नया 'एच' लोगो का इस्तेमाल किया जाएगा।

मॉडल भारत के अनुकूल बनाया गया

बयान के मुताबिक, इस मॉडल को शहरी और प्राकृतिक, दोनों तरह के परिवेश के अनुकूल बनाया गया है। भारत इस एसयूवी को पेश करने वाला पहला बाजार होगा। होंडा भारत में फिलहाल सिटी, अमेज और एलिवेट मॉडल का उत्पादन और बिक्री कर रही है। हाल में इसने प्रीमियम एसयूवी जेडआरवी को भी भारतीय बाजार में पेश किया है।

शौर्य भवन में शिफ्ट होंगे सैन्य अधिकारी

नई दिल्ली, आरएनएन। दिल्ली के ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक से भारतीय सेना और नौसेना के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की विदाई होने जा रही है। यह बदलाव केवल दफ्तरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भारत के सैन्य और रक्षा प्रशासन की कार्यप्रणाली में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है।

सात वरिष्ठ अधिकारी बैठेंगे, वॉर रूम भी बदलेगा

सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, उप सेना प्रमुख और सात प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स (पीएसओ) नवंबर के अंत तक दिल्ली कैंट स्थित नवनिर्मित शौर्य भवन में अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही सेना और नौसेना के प्रमुखों तथा उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साउथ ब्लॉक से काम करने की लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। साउथ ब्लॉक लंबे समय से रक्षा और सरकारी प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहां सेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारी रक्षा मंत्रालय के साथ एक ही परिसर में काम करते रहे हैं।

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की व्यवस्था में होगा बदलाव

नीट पीजी में पर्सेंटाइल की जगह रैंक आधारित व्यवस्था होगी लागू

विशेषज्ञ समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट

नई दिल्ली/संचार जगत



मेडिकल की स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों पर दाखिले की व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। नीट पीजी प्रवेश प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने मौजूदा पर्सेंटाइल आधारित पात्रता व्यवस्था को खत्म कर रैंक आधारित मेरिट व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है। समिति ने यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने नीट पीजी और सुपर स्पेशियलिटी प्रवेश परीक्षा (नीट एसएस) दोनों के लिए इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस संबंध में मसौदा नियम जारी किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद संबंधित पक्षों से सुझाव और राय मांगी जाएगी। समिति का मानना है कि दाखिला व्यवस्था में सुधार के साथ मेडिकल की पढ़ाई के न्यूनतम मानकों को भी बनाए रखना जरूरी है।

समिति ने मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जताई

विशेषज्ञ समिति ने कहा कि खाली सीटों की संख्या को देखते हुए सक्षम अधिकारियों ने पात्रता पर्सेंटाइल में कमी की है, लेकिन पीजी मेडिकल शिक्षा के न्यूनतम मानकों को बनाए रखना जरूरी है। समिति ने स्पष्ट किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्व को केवल प्रशासनिक औपचारिकता तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। विशेषज्ञ समिति ने पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों की खाली सीटों की समस्या दूर करने के लिए कई उपाय सुझाए हैं। समिति ने राज्य की फीस निर्धारण समितियों और सक्षम अधिकारियों से क्लिनिकल तथा गैर-क्लिनिकल विषयों के लिए अलग-अलग फीस व्यवस्था पर विचार करने को कहा है।

हवा में फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश

नई दिल्ली, आरएनएन। दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की एक उड़ान में सवार एक यात्री ने उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद कथित तौर पर इमरजेंसी दरवाजे के लीवर का कवर खोलने की कोशिश की, जिससे विमान में अलार्म बज गया। यह जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी। इस घटना के बाद, इंडिगो के एक क्रू मेंबर ने यात्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान पुणे जिले के सासवड निवासी 33 वर्षीय गौरव सत्येंद्र रौतेला के रूप में हुई है। वह इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई6884 से यात्रा कर रहा था और इमरजेंसी एग्जिट के बगल वाली सीट, 19डी पर बैठा था। पूछताछ में यात्री ने दावा किया कि उसने केवल उत्सुकतावश लीवर कवर को खोलने की कोशिश की थी, और उसे नहीं पता था कि यह इमरजेंसी दरवाजे से जुड़ा हुआ है।

दिल्ली से पुणे जा रहा था विमान, बड़ा हादसा टला

स्वदेशी बुलेट ट्रेन का मजबूती टेस्ट पूरा

नई दिल्ली, आरएनएन। भारत की पहली स्वदेशी हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन बी28 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। भारतीय रेलवे के अनुसार, इस बुलेट ट्रेन ने सुरक्षा मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है, जिसके तहत बेंगलुरु स्थित बीईएमएल (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) की निर्माण इकाई में इसका व्हीकल बॉडी शेल असेसमेंट (स्क्वीज टेस्ट) सफलतापूर्वक किया गया। बीईएमएल ऐसी दो स्वदेशी 8-कोच वाली बुलेट ट्रेनें तैयार कर रहा है। स्क्वीज टेस्ट में यह जांचा जाता है कि ट्रेन का बाहरी ढांचा किसी दुर्घटना या टक्कर की स्थिति में बिना आकार खोए या बिना क्षतिग्रस्त हुए अत्यधिक दबाव को सह सकता है या नहीं। क्योंकि यह ट्रेन बेहद तेज गति से चलेगी, इसलिए किसी भी संभावित दुर्घटना के समय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके बाहरी ढांचे का मजबूत होना बेहद जरूरी है।

दूरसंचार | 1 जनवरी 2027 से नियम होंगे लागू, कंपनियों के बीच ट्रैफिक का आदान-प्रदान भी नए तरीके से होगा

ट्राई का बड़ा बदलाव, अब आईपी आधारित होंगे कनेक्शन

नई दिल्ली/संचार जगत



देश में मोबाइल नेटवर्क और दूरसंचार कंपनियों के बीच कॉल कनेक्शन की व्यवस्था बदलने जा रही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नए दूरसंचार इंटरकनेक्शन नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे। इनका उद्देश्य अलग-अलग दूरसंचार नेटवर्क के बीच संपर्क को आसान और बेहतर बनाना है।

नए नियमों के तहत कंपनियों को पुराने इंटरकनेक्शन सिस्टम से नई तकनीक पर जाना होगा। इससे कॉल की गुणवत्ता, नेटवर्क की क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता बेहतर होने की उम्मीद है। नए इंटरकनेक्शन नियमों का नाम दूरसंचार इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 है। नए इंटरकनेक्शन अब आईपी आधारित होंगे। पुराने ई1/टीडीएम आधारित इंटरकनेक्शन को तीन साल में चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। अलग-अलग छोटे स्तर के इंटरकनेक्शन की जगह लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र यानी एलएसए स्तर पर ट्रैफिक का आदान-प्रदान होगा। इंटरकनेक्शन का मतलब दो या अधिक दूरसंचार नेटवर्क को आपस में जोड़ना है। इसी व्यवस्था से अलग-अलग कंपनियों के ग्राहक एक-दूसरे को कॉल कर पाते हैं। इसके लिए तकनीकी, परिचालन और व्यावसायिक इंतजाम किए जाते हैं।

आईपी आधारित इंटरकनेक्शन से क्या फायदा होगा

नए नियमों के तहत अब स्थापित होने वाले सभी नए इंटरकनेक्शन आईपी आधारित होंगे। वहीं, पुराने ई1/टीडीएम आधारित पीओआई को भी तीन साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। आईपी आधारित व्यवस्था में नेटवर्क के बीच इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक से संपर्क होगा। इससे बैंडविड्थ का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। कॉल की आवाज की गुणवत्ता सुधरेगी। कॉल शुरू होने से लेकर खत्म होने तक नेटवर्क का प्रदर्शन बेहतर होगा। इससे कम समय में कॉल जुड़ने और सेवा अधिक भरोसेमंद होने जैसे फायदे मिल सकते हैं। पीओआई की कॉल संभालने की क्षमता का आकलन एक साथ चल सकने वाले सेशन और लिंक की बैंडविड्थ के आधार पर होगा। सेवा की गुणवत्ता के तय मानकों का पालन भी जरूरी होगा।

बैंक गारंटी और भुगतान में देरी पर नई व्यवस्था

ट्राई ने मौजूदा बैंक गारंटी व्यवस्था को बरकरार रखा है। हालांकि, बैंक गारंटी के पुनर्मूल्यांकन की अवधि छह महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है। पीओआई के लिए बैंक गारंटी की अधिकतम सीमा तय करने का नया तरीका भी लागू होगा। इंटरकनेक्शन शुल्क या उसके इस्तेमाल के शुल्क के भुगतान में देरी होने पर ब्याज देना होगा। कंपनियां ब्याज दर आपसी सहमति से तय करेंगी। हालांकि, यह भारतीय स्टेट बैंक की एक साल की एमसीएलआर दर से दो प्रतिशत अधिक की सीमा से ऊपर नहीं हो सकेगी। नए नियमों में कंपनियों के लिए रिपोर्ट देना भी जरूरी होगा। उन्हें पुराने पीओआई से नए पीओआई पर ट्रैफिक स्थानांतरित करने और आईपी आधारित व्यवस्था अपनाने की जानकारी देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर चरणबद्ध वित्तीय दंड भी लगाया जा सकेगा।

ईडी की कार्रवाई

अनिल अंबानी की 510 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली, आरएनएन। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 510 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें 2 निजी विमान भी शामिल हैं। ईडी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। एजेंसी के मुताबिक, यह कार्रवाई रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (आरएएजी) से जुड़ी कंपनियों पर बैंक और वित्तीय संस्थानों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में की गई है।

इसमें 2 चार्टर्ड विमान और 6 प्लाट भी शामिल

संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी आदेश जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक कुर्क और जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 23,100 करोड़ रुपये हो गया है। ईडी की जांच में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से जुड़े 263.05 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला शामिल है।

स्पीकर देवनानी ने हिन्दी फिल्म 'देवी विज्ञानम' का ट्रेलर लॉन्च किया

संचार जगत



जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हिन्दी फिल्म 'देवी विज्ञानम' का ट्रेलर लॉन्च किया।

मुख्य अतिथि के रूप में देवनानी ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का विधिवत शुभारम्भ किया। समारोह में विधायक बाल मुकुन्दाचार्य, रविन्द्र सिंह भाटी सहित गणमान्य ने शिरकत की तथा कार्यक्रम का आयोजन उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। इस अवसर पर देवनानी ने फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं, जीवन मूल्यों और सामाजिक चेतना को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान आज के सन्दर्भ में सामायिक है। सनातन व विज्ञान का सामंजस्य है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं में ज्ञान एवं विज्ञान का विशेष महत्व रहा है। सिनेमा के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और जीवन दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि रचनात्मक एवं सार्थक सिनेमा समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने तथा भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देवनानी ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कलाकारों एवं समस्त तकनीकी टीम को उनके प्रयासों के लिए बधाई देते हुए फिल्म की सफलता की कामना की।

दीपावली पर वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजस्थान सरकार के व्यापक निर्देश

अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं शिक्षण संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध

7 एवं 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात्रि 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे ग्रीन पटाखे

संचार जगत

जयपुर। दीपावली के अवसर पर वायु प्रदूषण की रोकथाम, आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल राजस्थान के जिलों में पटाखों के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

निर्देशानुसार राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में शामिल अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, खैरथल-तिजारा एवं कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था लागू की गई है।

केवल CSIR-NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे आमजन

उक्त संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की शासन सचिव शैलजा देवल ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में केवल CSIR-NEERI (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति होगी। अन्य सभी प्रकार के पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन पटाखे चलाने के लिए 7 एवं 8 नवंबर, 2026 को दो निर्धारित समयावधियां तय की गई हैं। आमजन प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक तथा रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चला सकेंगे।

केंद्र-राज्य समन्वय मजबूत करने के लिए मुख्य सचिव ने नई दिल्ली में की 19 बैठकें

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव और शहरी विकास सचिव से की मुलाकात

राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के साथ दीपावली भोज में हुए शामिल

संचार जगत



जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अपने दो दिवसीय नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के साथ 19 बैठकें कीं। इन बैठकों में राजस्थान की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं, प्रशासनिक विषयों तथा केंद्र सरकार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। मुख्य सचिव ने मंगलवार को केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह से मुलाकात कर कार्मिक एवं प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के साथ आयोजित दीपावली भोज में भी भाग लिया। मुख्य सचिव ने नई दिल्ली स्थित संकल्प भवन में केंद्रीय शहरी विकास सचिव सतेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक में जयपुर मेट्रो, पीएम ई-बस सेवा तथा शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी शहरी निकायों ने स्वच्छता, सड़कों, स्ट्रीट लाइट और नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए 100 दिवसीय कार्ययोजनाएं तैयार की हैं। बैठक में जयपुर मेट्रो के विस्तार पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्य सचिव ने बताया कि बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक 3.80 किलोमीटर लंबे मेट्रो विस्तार का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबे मेट्रो के दूसरे चरण में 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं।

मुख्य सचिव ने पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के आठ शहरों में प्रथम चरण के लिए स्वीकृत 675 इलेक्ट्रिक बसों तथा दूसरे चरण में स्वीकृत 475 अतिरिक्त बसों की प्रगति से भी अवगत कराया। बैठक में बस डिपो और चार्जिंग सुविधाओं के विकास पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने जयपुर नगर निगम की जनभागीदारी आधारित पहल 'रंग दे गुलाबी' की जानकारी भी दी, जिसके दूसरे चरण में शहर के 150 वार्डों में 617 दीवारों का सौंदर्यीकरण किया गया है।

मुख्य सचिव ने दो दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान राजस्थान की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं से संबंधित लंबित विषयों के शीघ्र समाधान और केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों के साथ प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया।

पंचायतीराज आम चुनाव के तृतीय चरण में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 72.85 प्रतिशत रहा अंतिम मतदान

सांगानेर में सर्वाधिक 79.88 प्रतिशत तथा कोटखावदा में न्यूनतम 63.79 प्रतिशत रहा मतदान

संचार जगत

जयपुर। पंचायतीराज आम चुनाव के तृतीय चरण के तहत जयपुर जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मंगलवार को मतदान संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि जिले में कुल 72.85 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इस दौरान कुल 3,74,816 मतदाताओं में से 2,73,056 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि चाकसू में 72.99 प्रतिशत, कोटखावदा में 63.79 प्रतिशत,



माधोराजपुरा में 75.88 प्रतिशत, फागी में 70.29 प्रतिशत तथा



सांगानेर में 79.88 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इनमें सांगानेर पंचायत समिति क्षेत्र में सर्वाधिक 79.88 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि कोटखावदा में 63.79 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान के समयवार आंकड़ों की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रातः 10 बजे तक 17.38 प्रतिशत, दोपहर 1 बजे तक 39.59 प्रतिशत, अपराह्न 3 बजे तक 55.25 प्रतिशत तथा सायं 6 बजे तक 72.60 प्रतिशत तथा अंतिम रुप से मतदान प्रतिशत 72.85 प्रतिशत रहा।

निवाई पंचायत समिति चुनाव में 41 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन, आज नामांकन की अंतिम तिथि



संचार जगत

निवाई। पंचायतराज चुनाव 2026 को लेकर पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मंगलवार को 33 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। इसके साथ ही अब तक कुल 41 प्रत्याशियों की ओर से नामांकन पत्र जमा करवाए जा चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया के चलते मंगलवार को एसडीएम कार्यालय परिसर में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही। फार्म खरीदने एवं जमा करवाने के लिए पहुंचे लोगों के कारण कार्यालय परिसर में मेले जैसा माहौल नजर आया।

4 नवंबर को नामांकन की अंतिम तिथि

रिटर्निंग ऑफिसर गंभीर सिंह ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य पद के लिए भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी एवं निर्दलीय प्रत्याशियों सहित कुल 41 नामांकन दाखिल हुए हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। 5 नवंबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और अंतिम सूची जारी की जाएगी।

भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस जाप्ता रहेगा तैनात

रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन संभावित भीड़ को देखते हुए एसडीएम कार्यालय परिसर से 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुबह से ही भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहेगा, ताकि नामांकन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न करवाई जा सके।

युवक की ससुराल में मौत, परिजनों ने जताया संदेह



संचार जगत

देवली। शहर के प्रदीप नगर बोरड़ा रोड क्षेत्र में सोमवार रात 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने देवली थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर मौत के कारणों की जांच और खुलासे की मांग की है। देवली थाना प्रभारी प्रीति रत्नू ने बताया कि मृतक की पहचान टीकम पुत्र चंदराम बैरवा निवासी मेहरू कला, थाना सावर जिला अजमेर के रूप में हुई है।

टीकम बोरड़ा क्षेत्र स्थित अपने ससुराल में ससुर कालूराम के साथ खेत पर रहता था। हाल ही में वह अपने गांव गया था और वहां से सामान लेकर वापस आया था। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। पुलिस के अनुसार सोमवार रात युवक की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण कर एफएसएल टीम को बुलाया गया तथा साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने मौके से संबंधित जानकारी भी एकत्रित की।

मृतक के पिता चंदाराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा परिवार सहित बोरड़ा गणेशजी रोड पर शोजीराम के खेत में बटाई पर खेती का काम करता था। बेटे की मौत की सूचना मिलने के बाद पिता और अन्य परिजनों ने मौत के कारणों को लेकर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के जाहिरा चोट के निशान नहीं मिले हैं।

बेटियों की शिक्षा, संस्कार और आत्मनिर्भरता से सशक्त होगा राजस्थान

3.63 लाख बालिकाओं को मिले गार्गी पुरस्कार के तहत 109 करोड़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान ने बदली तस्वीर,

संचार जगत





जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बेटियां समाज और राष्ट्र की शक्ति हैं। जब बेटियों को शिक्षा, संस्कार, सम्मान और समान अवसर मिलते हैं, तो केवल एक बालिका ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार और समाज प्रगति करता है।

बालिका शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान ने देश में बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण के प्रति सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। राज्य सरकार भी शिक्षा को सर्वसुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के साथ बालिकाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मंगलवार को जयपुर के मानसरोवर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित प्रतिभा विकास शिविर समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, ऋषि-मुनियों, संतों और महापुरुषों ने हजारों वर्षों से समाज को जीवन मूल्यों और कर्तव्यों का संदेश दिया है। हमें अपनी गौरवशाली विरासत, महापुरुषों के आदर्शों और सांस्कृतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। केवल अधिकारों की बात करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना भी उतना ही आवश्यक है। माता-पिता, बुजुर्गों और परिवार के प्रति सम्मान एवं सेवा का भाव हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार की नीतियों से बालिकाओं के जन्म, शिक्षा एवं सामाजिक सहभागिता के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भी बालिकाओं को समान अवसर, सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर दिया गया है। बालिका शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, विचार और संस्कारों के निर्माण का आधार भी है।

राजीविका दिवाली मेले में सुबह 10 से रात 9 बजे तक प्रवेश निःशुल्क

राजीविका दिवाली मेले में खरीदारी का उत्साह चरम पर, बुधवार को खरीदारी का आखिरी मौका

संचार जगत



जयपुर। राजीविका दिवाली मेला-2026 में रौनक अपने चरम पर पहुंच गई है। मेले के सातवें दिन भी बड़ी संख्या में पहुंचे आगंतुकों ने विभिन्न स्टॉल्स पर जमकर खरीदारी की। विजिटर्स ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार हस्तनिर्मित उत्पादों, पारंपरिक हस्तशिल्प और आकर्षक सजावटी सामग्री को खूब पसंद किया। स्टॉल्स पर दिनभर खरीदारों की चहल-पहल बनी रही। दिवाली के त्योहार को खास बनाने के लिए आगंतुकों ने अपनी पसंद के अनुसार सजावटी सामान, पारंपरिक कलात्मक वस्तुओं और विभिन्न घरेलू उपयोग के उत्पादों की खरीदारी की। मेले में राजीविका दीदियों के हुनर, मेहनत और रचनात्मकता की झलक देखने को मिल रही है। यहां हस्तनिर्मित हस्तशिल्प, पारंपरिक कलात्मक वस्तुओं, आकर्षक सजावटी सामग्री, हैंडलूम और घरेलू उपयोग के उत्पादों की विविध रेंज उपलब्ध है। राजस्थान की समृद्ध लोककला और पारंपरिक शिल्पकारी को प्रदर्शित करते इन उत्पादों ने मेले को खास पहचान दी है। विभिन्न स्टॉल्स पर सजे रंग-बिरंगे उत्पादों के साथ खरीदारी कर रहे आगंतुकों का उत्साह मेले की रौनक को लगातार बढ़ा रहा है।

क्ले आर्ट और हैंडमेड क्राफ्ट ने जीता दिल

ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को मिल रहा प्रोत्साहन स्थानीय कला एवं हस्तशिल्प को नई पहचान देने के साथ महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रहा है। मेले में ब्लैक पॉटरी और ब्लू पॉटरी की आकर्षक कलाकृतियों के साथ सजावटी सामान, कोटा डोरिया, मोडल सिल्क, अजरख प्रिंट और बंधेज की साड़ियों एवं सूट की खूब मांग देखने को मिल रही है।

भाजपा पांच नवंबर को जयपुर में निकालेगी पैदल मार्च



संचार जगत

जयपुर। एसआईआर को लेकर सियासी घमासान के बीच भाजपा अब जयपुर की सड़कों पर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है। लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत पांच नवंबर को केंद्रीय रेल एवं सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में पैदल मार्च करेंगे। इस पदयात्रा में जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। भाजपा अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए देश भर में जनसभा और पदयात्राएं आयोजित कर रही है। पदयात्रा की शुरुआत रामलीला मैदान में जनसभा से होगी, जहां अश्विनी वैष्णव और पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं तथा आमजन को संबोधित करेंगे। इसके बाद रामलीला मैदान से चौड़ा रास्ता होते हुए त्रिपोलिया गेट तक करीब सवा किलोमीटर की सांकेतिक पदयात्रा निकाली जाएगी। खास बात यह है कि दीपावली की खरीदारी के चलते परकोटे के बाजारों में भीड़ को देखते हुए मार्च का रूट छोटा रखा गया है।

युवा भविष्य के नहीं, वर्तमान के राष्ट्र निर्माता : वासुदेव देवनानी

संचार जगत



जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और संघ के सचिव संदीप शर्मा ने राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के युवा संवाद का शुभारंभ किया। देवनानी की पहल पर विधान सभा सदन में आरम्भ हुए युवा संवाद का यह छठवां कार्यक्रम है। इस अवसर पर वासुदेव देवनानी ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी वास्तविक शक्ति युवा में निहित है। सशक्त संवाद-समर्थ भविष्य विषय पर आयोजित युवा सेमिनार में उन्होंने कहा कि युवा अब भविष्य के नागरिक ही नहीं, बल्कि वर्तमान के राष्ट्र निर्माता भी है। देवनानी ने कहा कि भारत आज विश्व में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। युवाओं की प्रतिभा, परिश्रम, नवाचार और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवा शक्ति की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवा देश के संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करें तथा राष्ट्र के प्राचीन वैभव और आधुनिक विकास के बीच समन्वय में भूमिका निभाएं। दो सत्रों में विभिन्न राज्यों के 17 शैक्षणिक संस्थानों के लगभग 110 युवाओं ने संवाद में अपनी बात रखी।

बस्तियों में सफाई रखने पर 201 महिलाएं सम्मानित

जयपुर। घुमंतू जाति उत्थान न्यास जयपुर महानगर और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका न्यूयॉर्क ने जयपुर में घुमंतू जाति बस्तियों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के अंतर्गत बस्तियों के घरों और आसपास की बस्तियों की सफाई रखने वाली 201 महिलाओं को घुमंतू जाति स्वच्छता पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जयपुर महानगर में मंगलवार को गालव भाग के तहत जयसिंहपुरा खोर दिल्ली रोड स्थित थाने के पीछे घुमंतू बस्ती में यह कार्यक्रम हुआ। दोनों संस्थानों की ओर से दीपावली से पहले जयपुर की बस्तियों में यह अभियान चंद्रा और केके मेहता फैमिली फाउंडेशन न्यूयॉर्क (अमेरिका) सहित डॉ. राज बंसल, डॉ. समीन शर्मा और डॉ. रोहित डांडिया के सहयोग से चलाया रहा है। न्यास के सहप्रांत संयोजक राकेश कुमार शर्मा ने बताया- कार्यक्रम में जयपुर की उपमहापौर सरोज कंवर का पार्षद सीमा पारीक ने स्वागत किया।

कैबिनेट सचिव से मिले मुख्य सचिव



संचार जगत

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन से मुलाकात की। मुख्य सचिव ने उन्हें राजस्थान में डिरेगुलेशन एंड कम्प्लायंस रिडक्शन तथा ज्ञान भारतम् मिशन की प्रगति से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव ने उन्हें बताया कि राजस्थान ने डिरेगुलेशन एंड कम्प्लायंस रिडक्शन के पहले चरण में आवंटित सभी 23 प्राथमिकता क्षेत्रों में कार्रवाई पूरी कर ली है। दूसरे चरण में आवंटित 28 प्राथमिकता क्षेत्रों में से 24 में की गई कार्रवाई पर केंद्र की सहमति प्राप्त हो चुकी है। शेष चार प्राथमिकता क्षेत्रों में से तीन में राज्य स्तर पर कार्यवाही जारी है, जबकि एक केंद्र स्तर पर विचाराधीन है। मुख्य सचिव ने ज्ञान भारतम् मिशन के तहत पांडुलिपियों के सर्वेक्षण एवं डिजिटलीकरण की प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 24 लाख 63 हजार 769 पांडुलिपियों का सत्यापित सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। लगभग एक लाख 61 हजार पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है तथा 19 केंद्रों पर यह कार्य जारी है।

हाईकोर्ट ने दिया आदेश

विद्याधर का बाग में अब नहीं गूंजेंगी शहनाइयां



संचार जगत

जयपुर। जयपुर में अब ऐतिहासिक विद्याधर का बाग में न शहनाइयां गूंजेंगी और न ही देर रात पार्टियों की रौनक देखने को मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस ऐतिहासिक बाग में शादी-समारोह, पार्टियों, रेस्टोरेंट और सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब यह इलाका रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, तो यहां रेस्टोरेंट चलाने के लिए टेंडर आखिर किस आधार पर जारी किया गया। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने सिटिजन्स प्रोटेक्शन सोसायटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि बाग में शादी-पार्टियों के दौरान देर रात तक तेज म्यूजिक, लेजर लाइट और आतिशबाजी से वन्यजीवों को नुकसान पहुंचता है। वहीं, सरकार ने कोर्ट को बताया कि साल 2022 में जारी रेस्टोरेंट संचालन का टेंडर समाप्त हो चुका है और फिलहाल कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही। इसके बावजूद कोर्ट ने ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एडवोकेट अपेक्षा बापना को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मौके की तस्वीरों सहित रिपोर्ट मांगी है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

राजस्थान में अब हर पेड़ की होगी पहचान



संचार जगत

जयपुर। राजस्थान में अब हर पेड़ की अपनी पहचान होगी। पेड़ों की कटाई पर निगरानी के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ऐसा आदेश दिया है, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब राजस्थान के शहरों और जिलों में पेड़ों की गणना होगी और हर पेड़ की जियो टैगिंग कर उसकी लोकेशन, प्रजाति और संख्या का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने सोमवार को जयपुर के चौमूं हाउस पार्क में करीब 800 विकसित पेड़ों की कथित अवैध कटाई के मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। आदेश के मुताबिक 25 से ज्यादा पेड़ काटने के प्रस्तावों की जांच एक उच्चस्तरीय समिति करेगी। समिति कटाई की जरूरत और औचित्य परखने के साथ पेड़ों को बचाने के विकल्प भी तलाशेगी। वहीं पेड़ काटने की अनुमति मिलने पर क्षतिपूरक पौधरोपण के तहत 10 से 100 गुना तक पौधे लगाने के विकल्प पर विचार होगा। इन पौधों की कम से कम पांच साल तक निगरानी भी करनी होगी। जिला कलेक्टरों को सक्षम अनुमति के बिना पेड़ कटाई रोकने और अवैध कटाई पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी ने यह भी कहा कि पुराने पेड़ों से खोई हरियाली दोबारा विकसित होने में 70 से 100 साल तक लग सकते हैं। चौमूं हाउस पार्क मामले में संयुक्त समिति छह सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपेगी।

मुख्य सचिव की पर्यावरण मंत्री से वार्ता

चंबल में अवैध रेत खनन और जोजरी नदी के प्रदूषण पर की चर्चा

संचार जगत



जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इंदिरा पर्यावरण भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव ने केंद्रीय मंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। बैठक में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन की रोकथाम और जोजरी नदी में प्रदूषण की समस्या पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में चंबल अभयारण्य के 40 संवेदनशील स्थानों पर 200 बॉर्डर होमगार्ड तैनात किए गए हैं तथा निगरानी के लिए कुल 65 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 से जून 2026 के दौरान अवैध रेत खनन एवं परिवहन के मामलों में 536 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 541 वाहन जब्त किए गए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा संबंधित विभागों की कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जा रही है। बैठक में जोजरी नदी तथा लूणी एवं बांडी नदी प्रणाली में औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्य सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जोधपुर में साझा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र और उससे जुड़ी 306 वस्त्र उद्योग इकाइयों का संचालन बंद है।

तेज रफ्तार गाड़ी ने कार को मारी टक्कर

जयपुर। जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर-7 में शनिवार देर रात हिट एंड रन का मामला सामने आया। रात करीब एक बजे तेज रफ्तार स्कोडा कार ने घर के बाहर खड़ी वोक्सवैगन कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वोक्सवैगन का पिछला टायर तेज धमाके के साथ फट गया और उसकी रिम भी चकनाचूर हो गई। टक्कर के बाद कार आगे लगे बिजली पोल से जा भिड़ी। इससे पोल भी टूट गया। हादसे के बाद स्कोडा सवार मौके से फरार हो गया। वोक्सवैगन कार मालवीय नगर सेक्टर-7 स्थित एसबीआई से रिटायर एजीएम शंकर लाल बुनकर की है। वह रोज अपनी कार घर के बाहर चारदीवारी के पास खड़ी करते हैं। शनिवार रात भी कार घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान गली में तेज रफ्तार से आई स्कोडा ने कार को जोरदार टक्कर मार दी।

जोराराम कुमावत ने किया जीत का दावा



संचार जगत

जयपुर। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि पंचायत राज चुनाव में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चरण में पंचायत राज चुनाव पूरे हो गए हैं, तीसरा चरण चल रहा है और फिर चौथा चरण भी होगा। पंचायत राज चुनाव में जिस तरह से जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी के ही सब जगह प्रधान और जिला प्रमुख बनेंगे। न्होंने कहा कि पिछले महीने जो नगर निकाय के चुनाव हुए उनमें से 204 नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली और भाजपा के बोर्ड बने। कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ढाई साल में राजस्थान के विकास के लिए काम किया उनमें किसान, मजदूर, महिलाओं और गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू करके समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को संबल देने का काम किया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया है। उससे जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताकर सरकार को और मज़बूती मिलेगी।

मिलावटखोरों पर प्रहार

35 हजार लीटर नकली घी के साथ फैक्ट्री सीज

संचार जगत



जयपुर। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग और स्वास्थ्य प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जैतपुरा इलाके में चल रही एक फर्जी डेयरी पैकिंग यूनिट का पर्दाफाश किया है। सीएमएचओ डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में टीम ने सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक चले लंबे ऑपरेशन में हिमालय डेयरी प्रोडक्ट्स नाम की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से राजस्थान सरस, डेयरी ब्रदर्स, श्री किरण सरस और माटुला जैसे आधा दर्जन से ज्यादा मशहूर ब्रांड्स के नाम पर पैक किया जा रहा था। छापे के दौरान टीम ने करीब 35 हजार लीटर संदिग्ध और मिलावटी घी बरामद किया। यह मिलावटी घी बाजारों में सप्लाई के लिए रखा गया था। मौके से केमिकल फ्लेवर भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल असली घी जैसी महक और स्वाद देने के लिए किया जा रहा था। टीम ने 35 हजार लीटर स्टॉक को मौके पर ही सीज कर दिया गया है और नमूनों को गहन जांच के लिए फूड लैब भेज दिया गया है।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना बनी पशुपालकों का संबल



संचार जगत

जयपुर। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक राहत प्रदान करते हुए अब तक 108 करोड़ रुपये से अधिक की बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल से पशुपालकों को पशुधन की सुरक्षा के साथ आर्थिक जोखिम से बचाव में सहायता मिल रही है। अब तक 18 लाख से अधिक पशुपालकों ने अपने 44 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण कराया है जिनमें से 30 लाख से अधिक पशुओं को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। 27.56 लाख पशुओं के लिए बीमा पॉलिसी जारी की जा चुकी है। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। प्रदेश के लाखों परिवारों की आजीविका पशुधन पर निर्भर है। ऐसे में पशुओं का बीमा पशुपालकों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।

जयपुर-50 फीट गहरे सूखे कुएं में महिला ने छलांग लगाई

संचार जगत

जयपुर। कॉन्स्टेबल तेजपाल ने बताया- मैं और महिला कॉन्स्टेबल राजकिरण सुबह पीसीआर पर तैनात थे। हमें सुबह 9 बजे कंट्रोल रूम से वायरलैस पर सूचना मिली थी कि चौंप गांव में एक महिला (50) कूएं में कूद गई। हमारी गाड़ी घटनास्थल से 8 किलोमीटर दूर थी। घटना की गंभीरता देखते हुए हम 9:18 बजे मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि 200 से 250 लोगों की भीड़ एकत्र थी। बोरिंग से पाइप खींचने वाली गाड़ी लगा रखी थी, लेकिन महिला को निकालने में सफलता नहीं मिली थी। कॉन्स्टेबल तेजपाल ने बताया- जब हम पहुंचे तो गांव वालों से समझाइश कर पहले भीड़ को दूर करवाया। फिर वहां से किसी को नीचे उतरने की गुजारिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। फिर गांव के एक घर से चारपाई मंगवाकर चारों कोने बांधकर कुएं में मैं खुद उतरा।

सीकर से 2 युवतियां लापता, मोबाइल भी स्विच ऑफ

सीकर। सीकर जिले में 29 साल और 25 साल की महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। दोनों के पति ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस अब दोनों की तलाश कर रही है। 29 साल की महिला के लापता होने के केस में उसके पति ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि वह 26 अक्टूबर को ड्यूटी करके जब अपने घर पर आया तो देखा की पत्नी घर पर नहीं है। घर में जो संदूक रखी हुई थी वह भी खुली थी। इसके बाद जब पूछताछ की तो पता चला की पत्नी तो अपने पीहर जाने की बात कह कर निकली थी। जब उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करना चाहा तो मोबाइल भी स्विच ऑफ था।

ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक के तहत हुआ आयोजन

संचार जगत



जयपुर। पर्यावरण संरक्षण एवं सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में एक से सात नवंबर तक ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक मनाया जा रहा है। विभाग के सभी 41 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना द्वारा विभागीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक के आयोजन के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत तथा स्थायी एवं पौष्टिक खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही एकल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने, ई-कचरे के उचित निस्तारण तथा अपशिष्ट को कम करने के उपायों के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। कार्यालयों में पौधारोपण, स्वच्छता अभियान तथा पर्यावरण एवं जल संरक्षण की शपथ दिलाने जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान में उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों की भी सक्रिय भागीदारी है।



संपादकीय

क्या संसद 'अवैध' है?

राजधानी दिल्ली के 'रामलीला मैदान' में विपक्ष के 21 दलों की साझा 'वोट चोरी' रैली सफल रही अथवा नहीं रही, हम इस पचड़े में फंसना नहीं चाहते, लेकिन देश भर में एक संदेश देने में विपक्ष जरूर सफल रहा है। यह संदेश है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ 'देशद्रोह' का केस चलाया जाएगा और उन्हें जेल में भेजा जाएगा। यह तभी संभव होगा, जब ज्ञानेश अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दें अथवा संसद में उनके खिलाफ 'महाभियोग' प्रस्ताव पारित हो जाए। फिलहाल दोनों ही स्थितियां संभव नहीं लगतीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि वे 'वोट चोरी' की आपराधिक साजिश में संलिप्त रहे हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह भी तभी संभव होगा, जब केंद्र में विपक्ष के 'इंडी' गठबंधन की सरकार होगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। सर्वोच्च अदालत भी कानूनी कार्रवाई पर फैसला दे चुकी होगी! फिलहाल इसके भी आसार नहीं हैं, बेशक विपक्ष कितनी भी हुंकारें भरता रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ये कथन सवालिया और गलत हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव 'अवैध' था। मतदाता सूचियों से 13.5 करोड़ नाम काट दिए गए। करीब 15 फीसदी मतदाताओं के नाम काट दिए गए। हर 7 में से 1 मतदाता का नाम हटा दिया गया, जबकि जीत-हार का अंतर मात्र 3 फीसदी था। राहुल गांधी ने यह गलत बोला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 19-20 फीसदी वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 38 फीसदी से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिला था। कांग्रेस के 99 सांसदों और अकेली भाजपा के 240 सांसदों की संख्या के बीच बहुत बड़ा फासला है। यदि 2024 का संसदीय चुनाव 'अवैध' था, तो सिर्फ प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और भाजपा सांसदों के ही चुनाव 'अवैध' नहीं थे, बल्कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसदों के निर्वाचन भी 'अवैध' हैं। लोकसभा के समूचे 543 सांसदों के चुनाव भी 'अवैध' हैं। क्या भारत जैसे लोकतंत्र और संवैधानिक देश में 'अवैध संसद' काम कर सकती है? क्या नेता प्रतिपक्ष का यह कथन देश के मतदाताओं, जनादेश, लोकतंत्र और संविधान का मजाक नहीं उड़ा रहा है? दरअसल यह खास किस्म की उत्तेजना, तैश, आवेश और कुंठा में बोला गया कथन है। चुनाव आयोग ने 28 अक्तूबर, 2025 को 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) का अभियान बिहार से शुरू किया था, तो मई-जून, 2024 के लोकसभा चुनाव में किसने और कैसे 'वोट चोरी' की? एसआईआर कर्नाटक, तेलंगाना, केरल में भी किया गया है, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। गौरतलब यह है कि जनवरी, 2024 में सहकारी सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता को 15 मार्च को, सुखबीर सिंह संधु के साथ, चुनाव आयुक्त के संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया था।

ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगती कांग्रेस को नया झटका, सारे खेल बिगाड़ देंगे मोदी-शाह?

तमाम वैश्विक जोखिमों और एल नीनो जैसे मौसमी और आर्थिक संकटों के बावजूद, भारत की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। दुनिया भर के वित्तीय विश्लेषक हैरान हैं कि कैसे ग्लोबल क्राइसिस और युद्ध के माहौल के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा. भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है।

एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष का आरोप, वोट चोरी हो रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल और है। देश की अर्थव्यवस्था, गरीबों की जिंदगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय सुरक्षा में आखिर क्या बदलाव आया, क्योंकि राजनीति सिर्फ आरोपों से नहीं चलती। राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली के जरिये ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा। नरेंद्र मोदी को हरा ना पाने के अकुलाहट में राहुल गांधी एंड टीम गजब काम करती जा रही है। इस रैली को लेकर दिल्ली के कारोबारी कहते रह गए कि ये वक्त त्योहारों का है, इस वक्त रैली धरना प्रदर्शन मार्च करोगे तो काम धंधे पर असर पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी ने इसे सुना नहीं। न राहुल गांधी ने उनकी इस मांग पर ध्यान दिया जो मैसेज बैलेट वाले चुनाव में मिला है। इस रैली के जरिये जनता ने राहुल गांधी के नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद भी राहुल गांधी इंडी और इंडी का इकोसिस्टम लगा हुआ है कि मोदी के खिलाफ माहौल बनाना है। इसके लिए फिर जो चाहे करना पड़े वो करेंगे। जबकि लोग पूछ रहे हैं कि जब एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इलेक्शन कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर सड़कों पर क्यों गदर मचाया जा रहा है। सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर सड़कों पर रोज रोज का तमाशा करके राजनीति को क्यों चमकाया जा रहा है। एक नवंबर की तारीख दिन भर सुर्खियों में रही। दिल्ली में एक तरफ विपक्षी गठबंधन की महारैली थी। दूसरी तरफ सिख दंगों के खिलाफ बीजेपी का पैदल मार्च। और तीसरी तरफ बीजेपी का जारी किया वीडियो, जिसमें इंडी गठबंधन



की रैली को फ्लॉप बताया गया। राहुल गांधी ने रैली में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया था, लेकिन बीजेपी ने कहा कि 40 फीसदी मैदान खाली रहा। लोग राहुल के भाषण के बीच से निकल गए। ये लोग नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन विकास के काम कैसे होता है, इसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वर्ल्ड बैंक तक तारीफ कर रहा है। भारत में गरीबी हटाने के नारे इंदिरा गांधी के जमाने से दिए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों का जीवन सुधारने के लिए पीएम मोदी ने जो किया आज उसकी चर्चा वर्ल्ड बैंक तक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी तेजी से घट रही है। 2011 से 2023 के बीच 49.6 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं। ये बहुत बड़ा काम है। बात सिर्फ इसी की नहीं है, डेवलमेंट से लेकर इकॉनमी और डिफेंस तक जबरदस्त काम हो रहे हैं। ग्लोबल क्राइसिस और युद्ध के माहौल के बीच इकॉनमी की रफ्तार पर लगातार बढ़ती जा रही है। घरेलू स्तर पर लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और बाहरी स्तर पर देश की सुरक्षा अभेद बनी रहे, इसके लिए काम हो रहे हैं। यानी उधर राहुल गांधी का नैरेटिव और इधर नरेंद्र मोदी के गजब काम। देश में यही तो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष का आरोप, वोट चोरी हो रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल और है। देश की अर्थव्यवस्था, गरीबों की जिंदगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय सुरक्षा में आखिर क्या बदलाव आया, क्योंकि राजनीति सिर्फ आरोपों से नहीं चलती। राजनीति का असली इम्तिहान होता है- काम, नतीजे और लोगों की जिंदगी में आया बदलाव, और अब भारत की गरीबी में आई गिरावट को लेकर वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2023 के बीच भारत में करीब 49.6 करोड़ लोग गरीबी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मानक से ऊपर आए, दूसरी तरफ आईएमएफ ने वैश्विक तनाव और ऊर्जा संकट के बीच भी भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7 फीसदी किया है और डिफेंस में भारत का रक्षा बजट 2013-14 के करीब 2.53 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, स्वदेशी हथियार और तकनीक के दम पर भारत ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना जीएसएलवी -एफ 18 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह एनवीएस-03 को अपने साथ ले गया है। अमेरिका पर अब भारत की निर्भरता नहीं रहेगी। तो सवाल है कि क्या भारत की कहानी सिर्फ चुनावी आरोपों तक सीमित है, या देश के भीतर और दुनिया की नजर में कुछ बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के रामलीला बैठकर कोई वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ रहा है, कोई संसद से सड़क तक हंगामा खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम बोल रहा है। राजनीति दो तरह से होती है, एक वो जो दशकों तक सिर्फ नारे देती रही, और दूसरी वो जो धरातल पर नतीजे लाकर पूरी दुनिया को चौंका देती है। गरीबी हटाने का नारा इस देश में नया नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी के दौर तक गरीबी हटाओ के बड़े-बड़े मंच सजाए गए, लेकिन गरीबी हटी या गरीब वही का वही रहा। इसका जवाब आज दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था यानी वर्ल्ड बैंक दे रही है। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है कि भारत में साल 2011 से 2023 के बीच 49.6 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी के जाल से बाहर निकल चुके हैं. जो काम 50 सालों में नारों के दम पर नहीं हो सका, वो नरेंद्र मोदी के 10-12 सालों के विजन और नीतियों से संभव हुआ है. आज पूरी दुनिया भारत के इस ट्रांसफॉर्मेशन का लोहा मान रही है।

मुनाफाखोरी की गिरफ्त में मरीज

भारत ने पिछले तीन दशकों में चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। दुनिया की हर पांच में से एक जेनेरिक दवा भारत में बनती है। इसलिए भारत को 'विश्व फार्मेसी' कहा जाता है। भारत ग्लोबल साउथ सहित कई देशों के लिए चिकित्सा पर्यटन का विश्वसनीय केंद्र भी है, लेकिन इस उपलब्धि के पीछे एक चिंताजनक तस्वीर भी है, जो हमारे मेडिकल स्टोर पर रोज दिखाई देती है। यह तस्वीर दवाओं की ऊंची कीमतों और उससे भी गंभीर नकली तथा घटिया दवाओं के बढ़ते कारोबार की है। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि नैतिक संकट भी है, जहां मुनाफे की लालसा जीवन के मूल्य पर भारी पड़ रही है। ध्यान देने योग्य है कि दवाओं की कीमत और गुणवत्ता केवल उनके निर्माण की लागत और वैज्ञानिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि निर्माता से मरीज तक पहुंचने वाली आपूर्ति व्यवस्था से भी प्रभावित होती है। इसी क्रम में नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथारिटी (एनपीपीए) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने कैंसर की 137 गैर-अनुसूचित दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन लागू किया है। ये दवाएं अब तक मूल्य नियंत्रण के दायरे में नहीं थीं। एनपीपीए की जांच में सामने आया कि इन दवाओं पर 700 प्रतिशत तक ट्रेड मार्जिन वसूला जा रहा था।



उदाहरण के लिए, कंपनी जिस दवा को 10 हजार रुपये में स्टाकिस्ट को बेचती थी, उसका अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 50 हजार रुपये तय किया जाता था। यानी बिचौलियों, वितरकों, अस्पतालों की फार्मेसी और करों के नाम पर कीमत में 40 हजार रुपये का अंतर था। सरकार ने ट्रेड मार्जिन को एमआरपी के अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। इससे एमआरपी में 70 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है। इसी व्यवस्था के तहत एनपीपीए ने 2019 में 42 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को नियंत्रित किया था। तब उनकी कीमतों में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी। मार्जिन सीमित करने का अर्थ कंपनियों की कमाई घटाना नहीं है। निर्माता को उसका निर्धारित मूल्य मिलता रहेगा, जबकि बिचौलियों का असामान्य मुनाफा घटेगा। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि मूल्य नियंत्रण से नवाचार प्रभावित होगा। यहां एक सवाल यह है कि क्या केवल ट्रेड मार्जिन सीमित करने से कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज सस्ता हो जाएगा? ट्रेड मार्जिन को नियंत्रित करना और निर्माता द्वारा तय की गई कीमत को नियंत्रित करना दो अलग-अलग पहलू हैं। यदि निर्माता शुरुआती कीमत ही बहुत अधिक तय करता है, तो 30 प्रतिशत मार्जिन की सीमा के बाद भी दवा महंगी रहेगी। इसके अलावा कंपनियां 'आर्टिफिशियल डिस्काउंट' का तरीका भी अपनाती हैं। वे चुनिंदा बड़े कारपोरेट अस्पतालों को कुछ यूनिट पर भारी छूट देकर कम बाजार मूल्य का आभास देती हैं, जबकि बाकी दवाएं ऊंची कीमत पर ही बिकती हैं। इससे नियामक के लिए दवा का वास्तविक बाजार मूल्य तय करना कठिन हो जाता है। इसलिए ट्रेड मार्जिन नियंत्रण के साथ कीमतों की सख्त निगरानी और बिक्री तथा छूट की पारदर्शी रिपोर्टिंग भी जरूरी है। यह व्यवस्था सभी दवाओं पर लागू होनी चाहिए। नकली और घटिया दवाओं की समस्या महंगी दवाओं से भी जुड़ी है। जब दवाएं बहुत महंगी हो जाती हैं तो नकली दवाओं के लिए बाजार तैयार हो जाता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अनुसार, बाजार में तीन से पांच प्रतिशत दवाएं मानक गुणवत्ता से कम या नकली हैं। सरकार को कानून और तकनीक के जरिये नियमन एवं निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। एनपीपीए को स्वास्थ्य संस्थानों और अन्य संबंधित पक्षों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जो चार पहलुओं पर नजर रखे-मरीज का कुल बिल, दवाओं की उपलब्धता, अस्पतालों की बिलिंग और इलाज तक पहुंच। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कीमतें घटने के बाद संबंधित दवाएं दूरदराज के क्षेत्रों में उपलब्ध रहें, क्योंकि कंपनियां अक्सर कम मुनाफे वाली पुरानी दवाओं का उत्पादन बंद कर देती हैं। अब 300 से अधिक दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य है, जिसे स्कैन करके असली और नकली दवा की पहचान की जा सकती है। इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन कर नकली दवा बनाने को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है।

जलवायु वित्तपोषण की भारी कमी और जीवाश्म ईंधन बने कॉप-31 के लिए बड़ी बाधा

अगले सप्ताह 90 देशों के नेता संयुक्त राष्ट्र ज?लवायु परिवर्तन सम्मेलन के 31वें संस्करण (कॉप-31) में शामिल होने के लिए तुर्किये के खूबसूरत तटीय शहर अंताल्या पहुंचेंगे। हालांकि वहां से किसी अच्छी खबर की उम्मीद कम ही है। यह तो तय है कि 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल होने की संभावना नहीं है। समझौते के तहत वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को औद्योगिक युग से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था। पिछले साल नवंबर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि अगले दशक के भीतर ही वैश्विक तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की निचली सीमा को पार कर जाएगी। इसकी प्रमुख वजह जीवाश्म ईंधनों का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पिछले 20 लाख वर्षों के किसी भी समय की तुलना में अब अधिक है। इस बात पर भी संदेह है कि सभी देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल कर



पाएंगे। यदि सभी देश प्रतिबद्धताओं को पूरा भी कर लें तब भी इस सदी के अंत तक दुनिया का तापमान 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस भयावह परिदृश्य के मद्देनजर अंताल्या सम्मेलन में प्रयास यह होगा कि वैश्विक तापमान वृद्धि को पहले अधिकतम 1.7-1.8 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने और फिर वर्ष 2100 तक घटाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लाने का लक्ष्य हासिल किया जाए। इसके लिए पेरिस समझौते के समय किए गए वादों की तुलना में उत्सर्जन में कहीं अधिक कटौती की प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होगी। जीवाश्म ईंधन के बेरोकटोक इस्तेमाल के अलावा विकसित देशों की लगातार अनिच्छा भी एक बड़ी बाधा है। ये देश वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब और विकासशील देशों में न्यूनीकरण और अनुकूलन परियोजनाओं के लिए तत्काल आवश्यक वित्तीय सहायता देने से हिचकते रहे हैं। डॉनल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते को खारिज करने से इस रुझान की शुरुआत हुई थी। उनके दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने भी जलवायु वित्तपोषण की पहलों से बड़े पैमाने पर हाथ खींच लिया। इस तथ्य को काफी प्रचारित किया गया है कि जलवायु वित्त का सालाना आंकड़ा 2 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। लेकिन यह वर्ष 2030 तक आवश्यक हर साल 7.8 लाख करोड़ डॉलर की राशि से बहुत कम है। इस सीमित वित्त का बड़ा हिस्सा न्यूनीकरण परियोजनाओं (जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन में कटौती) पर खर्च होता है जिनसे राजस्व अर्जित करने की संभावना रहती है। इसके कारण अनुकूलन कार्यक्रमों के लिए बहुत कम धन बचता है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। उसने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित समय से नौ साल पहले ही हासिल कर लिया। उत्सर्जन की तीव्रता में कमी का लक्ष्य भी तय समय से 10 साल पहले पूरा कर लिया और अब वह एक अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इस उपलब्धि के आधार पर भारत ने वर्ष 2031 से 2035 के लिए महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य तय करने का आत्मविश्वास हासिल किया है। इन उपलब्धियों का आकलन लगातार हो रहे पारिस्थितिक विनाश के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए ।

क्रमिक प्रभावः बांध और भूमि अधिकार

अरुणाचल प्रदेश में 11.2-गीगावाट क्षमता वाली 'सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना' (एसयूएमपी) को नौकरशाही की तरफ से तेजी से आगे बढ़ाने के पीछे कथित तौर पर चीन द्वारा तिब्बत में 60-गीगावाट क्षमता वाले के एक विशाल बांध के आक्रामक तरीके से किए जा रहे विकास का हाथ है। चीन के इस कदम से भारतीय अधिकारियों के बीच इस बात की चिंता पैदा हो गई है कि कहीं सीमा पार बहने वाले पानी का इस्तेमाल एक 'हथियार' के रूप में न किया जाए। बीजिंग यारलुंग त्सांगपो नदी, जो भारत में ब्रह्मपुत्र बन जाती है, के बहाव की दिशा बदल सकता है जिससे नदी के निचले इलाकों में सूखा पड़ सकता है या फिर वह एक साथ बहुत सारा पानी छोड़ सकता है जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में भयानक बाढ़ आ सकती है। लिहाजा नई दिल्ली एसयूएमपी को एक रणनीतिक बफर के रूप में देखती है। लेकिन ऐसा करने के क्रम में उसके सामने एक ऐसी दुविधा खड़ी हो गई है जिसे सुलझाने के लिए उसे ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी मौजूदा 'ऊपर से नीचे' (टॉप-डाउन) वाली कार्यशैली - जिसका नजारा सर्वे टीमों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों को तैनात करने और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर 'राज्य गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' लादने में दिखाई देता है - स्थानीय लोगों के इस डर को और पुख्ता करती है कि सरकार उनकी जमीन हड़प लेगी। इस इलाके में सुबनसिरी ऊपरी पनबिजली परियोजना के खिलाफ लगातार विरोध-प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के पनबिजली आधारित विकास मॉडल पर सवाल खड़े करते हैं। पूर्वी हिमालय दुनिया के सबसे ज्यादा विवर्तनिक रूप से सक्रिय और कटाव की दृष्टि से संवेदनशील भू-भागों में से एक है। तिब्बत में बनने वाले इस विशाल बांध में पांच क्रमिक बिजली केंद्र होंगे, जो नदी के 50 किलोमीटर के दायरे में लगभग 2,000 मीटर की ढलान पर स्थित होंगे। बीजिंग का कहना है कि इस बांध से नदी के बहाव की दिशा में पड़ने वाले देशों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसने इंजीनियरिंग से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग के विवादित दावों के अलावा, एसयूएमपी के संचालन में कूटनीति एक अहम हिस्सा होगी।असम और बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र बेसिन को अपना अधिकांश पानी मानसूनी बारिश और तिब्बती पठार के नीचे की ओर स्थित सहायक नदियों से मिलता है। इसलिए, चीन भारत से होकर बहने वाली इस नदी के कुल प्रवाह को सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर भी, चूंकि सीमा के करीब चीन के हस्तक्षेप के नतीजे ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, लिहाजा एसयूएमपी को अपनी कार्ययोजना बनाने के लिए उक्त विशाल-बांध के संचालन और नीचे की ओर आने वाले पानी के प्रवाह, दोनों के बारे में जानकारी की जरूरत होगी। लेकिन बीजिंग ने बांध के संचालन से जुड़ी जानकारियां साझा करने से इनकार कर दिया है। इस तरह, एसयूएमपी को शुरुआत से ही कई अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत द्वारा चीन के समक्ष उच्च स्तर पर बार-बार यह मुद्दा उठाने के बावजूद, सिर्फ इतनी ही प्रगति हुई है कि बीजिंग आपातकालीन स्थितियों में मानवीय आधार पर जल-संबंधी (हाइड्रोलॉजिकल) डेटा साझा करने को राजी हो गया है। योजनाकारों ने अचानक पानी का स्तर बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए एसयूएमपी जलाशय को 70 फीसदी क्षमता पर रखने पर विचार किया है। लेकिन अगर चीन पहले से कोई चेतावनी नहीं देता है, तो उस सूरत में मिल पाने वाली सुरक्षा को लेकर स्थिति साफ नहीं है। यह अनिश्चितता सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। खासकर वैसी सूरत में, जब आदि समुदाय के लोगों और नागरिक अधिकार समूहों की ओर से इस परियोजना का जायज विरोध भी हो रहा है। किसी परियोजना की जरूरत होने का मतलब यह नहीं है कि सरकार सभी संबंधित कानूनों और सुरक्षा नियमों का पालन न करे। सरकार देश के लोगों को नाराज करके देश की जरूरतों की रक्षा नहीं कर सकती।

लघु कथा

सच्ची दौलत

एक छोटे से गाँव में रोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। एक दिन वह रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे सड़क पर एक चमचमाता हुआ पर्स मिला। रोहन ने उसे खोलकर देखा, तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और कुछ पैसे थे। उसकी पहली इच्छा हुई कि वह इन पैसों से अपने और अपने परिवार की गरीबी दूर कर ले। लेकिन तभी उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा, 'यह मेहनत की कमाई तुम्हारी नहीं है। इसे खोकर कोई बहुत परेशान हो रहा होगा।' रोहन ने बिना किसी लालच के वह पर्स गाँव के सरपंच को सौंप दिया। सरपंच ने पूरे गाँव में घोषणा करवाई, तो कुछ ही घंटों में एक अमीर व्यापारी वहाँ आया। व्यापारी बहुत घबराया हुआ था। उसने बताया कि वह अपनी सारी जमा-पूँजी का पर्स कहीं गिरा



चुका है। रोहन ने वह पर्स सही-सलामत व्यापारी को सौंप दिया। व्यापारी रोहन की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने इनाम के रूप में उसे कुछ सिक्के देने चाहे, पर रोहन ने मना कर दिया और कहा, 'ईमानदारी मेरा फर्ज है, इनाम नहीं।' व्यापारी ने रोहन की पीठ थपथपाई और कहा, 'दौलत तो आज नहीं तो कल कमाई जा सकती है, पर तुम्हारी जैसी ईमानदारी बहुत दुर्लभ है।

त्रिपुरा में बीएसएफ जवानों पर हमले के आरोप में आठ आरोपी गिरफ्तार

संचार जगत



अगरतला। त्रिपुरा के सेपाहीजाला जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास अशाबारी में सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर हमला करने के आरोप में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार को बीएसएफ जवानों ने कलामचौरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आशाबारी में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास कुछ भारतीय और बांग्लादेशी तस्करों को अवैध गतिविधियों में शामिल होते देखा। जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और एक भारतीय तस्कर को पकड़ लिया। हालांकि, जब बीएसएफ जवान वहां पहुंचे, तो सीमा बाड़ के दूसरी तरफ मौजूद बांग्लादेशी तस्कर भाग गए। पकड़ा गया भारतीय तस्कर भी किसी तरह भाग निकला और उसने ग्रामीणों से कहा कि बीएसएफ जवानों ने उसके साथ मारपीट की है। इसके बाद बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं मौके पर जमा हो गए। उन्होंने बीएसएफ की गाड़ी को घेर लिया और लाठी-डंडों से जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें कंपनी कमांडर समेत तीन जवान घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने एक बीएसएफ जवान की राइफल छीनने की भी कोशिश की। भीड़ ने बीएसएफ की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना में हमलावरों में से एक व्यक्ति भी घायल हो गया।सूचना पर बीएसएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। हालांकि, इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है।

अमित शाह के दौरे के बाद चंडीगढ़ की राजनीति गरमाई

संचार जगत



चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे और दिसंबर में प्रस्तावित नगर निगम चुनाव को देखते हुए शहर की राजनीति गरमा गई है। गृह मंत्री की ओर से चंडीगढ़वासियों की लंबे समय से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिए जाने और इसकी औपचारिक घोषणा की जिम्मेदारी पंजाब के राज्यपाल एवं प्रशासक गुलाब चंद कटारिया पर छोड़ने के बाद शहर में सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। तीनों दल गृह मंत्री के दौरे को लेकर अपने-अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस ने गृह मंत्री के दौरे को शहर के लिए निराशाजनक बताते हुए कहा है कि चंडीगढ़ को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने इसे झूठे आश्वासनों की राजनीति करार दिया है, जबकि भाजपा ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ में 500 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में योगदान का दावा किया है। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि गृह मंत्री के दौरे से शहर को कुछ नहीं मिला और चंडीगढ़वासियों को खाली हाथ रहना पड़ा। वहीं, आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि चंडीगढ़ की जनता को केवल झूठे आश्वासन मिले हैं। हर बार नेताओं के दौरे होते हैं, लेकिन आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। दूसरी ओर, भाजपा महासचिव रामवीर भट्टी ने कांग्रेस और आप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चंडीगढ़ को केंद्र सरकार से बहुत कुछ मिला है। गृह मंत्री ने शहर में 500 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति केवल अखबारों तक सीमित है। तीनों राजनीतिक दलों के अलग-अलग दावों ने शहर में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस और आप जहां गृह मंत्री के दौरे के बाद चंडीगढ़ को कोई ठोस सौगात नहीं मिलने का आरोप लगा रही हैं, वहीं भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिना रही है।

धीरेंद्र शास्त्री की कृष्ण पर टिप्पणी से सियासी बवाल

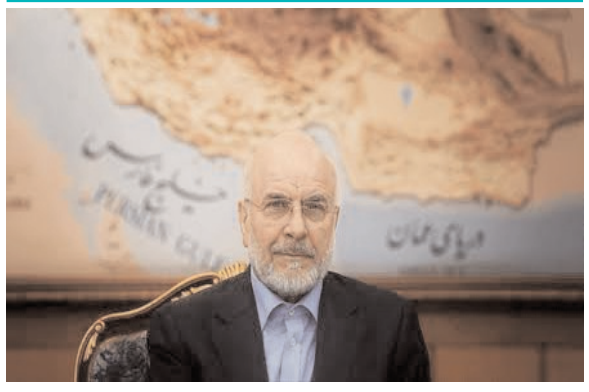
संचार जगत



नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में श्री राम कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री द्वारा भगवान राम और भगवान श्रीकृष्ण की तुलना को लेकर दिए गए बयान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भगवान कृष्ण के स्वरूप, उनके खड़े होने और टेढ़े होने को लेकर की गई टिप्पणी के बाद विपक्षी नेताओं ने उन्हें जमकर घेरा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मानवीय भूलों के लिए तो क्षमा किया जा सकता है, ईशनिंदा के लिए कभी नहीं। ऐसे दुष्मुखी लोगों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना ही समाज के लिए श्रेयस्कर है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी लिखा कि यह बिल्कुल बेतुकी बात है। संत सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास के बीच का संवाद, दरअसल, एक ही भगवान विष्णु के अलग-अलग स्वरूपों के प्रति भक्ति का संवाद था। राजद नेता तेजस्वी यादव ने लिखा कि लोक एकता की कनिष्ठ अंगुली से इंद्रासन को हिला देने वाले लोकनायक, धार्मिक सीमाओं से परे जन जन के पूज्य, हमारे कुलदेवता भगवान श्री कृष्ण पर सत्ता-पोषित एक मानसिक विक्षिप्त द्वारा की गई टिप्पणी अशोभनीय, अक्षम्य एवं अमर्यादित है। एम-टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मामले में भाजपा की तीखी आलोचना की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोई तो केमिकल लोचा है। इनकी जांच करवाना ठीक होगा। बढ़ते विवाद को देखते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है।

जंग रोकने की जिम्मेदारी हमारी नहीं

गेंद अब अमेरिका के पाले में : गालिबाफ



संचार जगत

तेहरान। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने जंग रोकने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका के हवाले कर दी है। मंगलवार को संसद के एक खुले सत्र में कहा कि वो अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। गालिबाफ ने कहा कि क्षेत्रीय देशों को यह पता होना चाहिए कि ईरान ने अमेरिकी पक्ष को एक मजबूत और तर्कसंगत जवाब दिया है, और अब युद्ध रोकने के लिए गेंद अमेरिका के पाले में है। उन्होंने कहा कि ईरान ट्रिगर पर उंगली रखे लड़ाई के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि वाशिंगटन की ओर से की गई कोई भी रणनीतिक गलती अमेरिकी सैनिकों को एक नए युद्ध के मैदान में उतरने के लिए मजबूर कर देगी। उन्होंने कहा कि ईरान के अटल रवैए और हार न मानने वाले जज्बे ने इजरायली और अमेरिकी प्रशासन को हताशा की गर्त में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि हम मैदान और सैन्य क्षेत्र में अपनी रक्षा तैयारियों को सर्वोच्च स्तर पर रखते हैं। अगर वाशिंगटन कोई और रणनीतिक गलती करता है, तो उसे जान लेना चाहिए कि इस बार उसे एक बिल्कुल नए युद्ध क्षेत्र का सामना करना पड़ेगा।

अमित शाह 5 नवंबर को हरियाणा दौरे पर

संचार जगत

चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को करनाल और अंबाला में दो कार्यक्रमों के लिए हरियाणा आएंगे। इस दौरान वे करनाल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बताया कि इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के आरोपों की सच्चाई जनता के सामने लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वह देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि चुनाव आयोग देश की जनता के वोट काटने का काम कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी दल मिलकर देश की जनता के बीच इसका जवाब देने के लिए आ रहे हैं ताकि भ्रम की स्थिति दूर की जा सके। इसके बाद अमित शाह अंबाला में बड़े स्मारक का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद सभा को संबोधित करेंगे।

बायोइकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए तेज मंजूरियां और आसान फंडिंग जरूरी: पीयूष गोयल

संचार जगत



नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य पीयूष गोयल ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नियामकीय मंजूरियों की प्रक्रिया तेज करने, स्टार्टअप्स के लिए वित्तपोषण को आसान बनाने और उद्योग तथा शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया है। भारत की बायोइकॉनॉमी का अवसरः नवाचार और विकास को बढ़ावा देने में स्टार्टअप्स की भूमिका' विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय राउंडटेबल बैठक की अध्यक्षता करते हुए गोयल ने कहा कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता और उद्यमशील प्रतिभा का बेहतर उपयोग कर देश को वैश्विक बायोइकोनॉमी क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सकता है। बैठक के दौरान गोयल ने सामने आए सुझावों पर समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। चर्चा का मुख्य फोकस बायोफार्मा स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए नियमों को सरल बनाना, मंजूरी प्रक्रियाओं को तेज करना, पूंजी तक पहुंच बढ़ाना और साझा बुनियादी ढांचे का विकास करना था। बैठक में प्रतिभागियों ने एक प्रस्तावित रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, वैश्विक नियामकीय मानकों के साथ बेहतर तालमेल और पेटेंट आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे उपायों पर चर्चा की। इन कदमों का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स को तेजी से विस्तार करने में मदद करना है। राउंडटेबल में जीवन विज्ञान क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण को मजबूत करने, प्रयोगशाला उपकरणों और रसायनों के आयात हेतु सीमा शुल्क मंजूरियों को तेज करने तथा सरकारी योजनाओं और नियामकीय समर्थन तक पहुंच को आसान बनाने जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल

आठ इलाकों में एक्यूआई 400 पार



संचार जगत

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सांस लेना अब मुश्किल होता जा रहा है। वहां की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है। मंगलवार सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई 332 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं, राजधानी के आठ मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया। इनमें जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा 452, रोहिणी में 429, पंजाबी बाग में 425 और बवाना में 408 एक्यूआई दर्ज किया गया। यानी इन इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी के दूसरे चरण की पाबंदियां भी लागू कर दी हैं। इसके तहत सड़कों की मैकेनिकल सफाई, पानी का छिड़काव और प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।

कीर्ति आजाद को सुप्रीम कोर्ट से झटका

याचिका पर सुनवाई से इनकार के बाद वापस ली अर्जी



संचार जगत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और ममता-तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके बाद उनके वकील ने याचिका वापस ले ली है। कीर्ति आजाद ने अपने खिलाफ दर्ज कथित जबरन वसूली के मामले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका पर सुनवाई की अनुमति नहीं देगा क्योंकि गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की मांग को लेकर उनकी अर्जी पहले से ही कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित है और हाईकोर्ट उन्हें अंतरिम राहत भी दे चुका है। गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में कीर्ति आजाद को कथित जबरन वसूली के मामले में छह महीने तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है। कीर्ति आजाद पर एक कारोबारी को धमकाने, उससे जबरन वसूली की रकम मांगने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं। इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को बताया परिवारवाद की पार्टी

कहा सत्ता की तिलमिलाहट में नेता हो रहे परेशान

संचार जगत



नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की परिवारवाद की राजनीति, संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए जा रहे आरोपों, देश की संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति कांग्रेस नेताओं के दृष्टिकोण पर तीखा हमला बोला। नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। पार्टी के स्वयं के लोग ही अब उसे नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की नाराजगी और बेचैनी का कारण सत्ता नहीं मिलना है। कुर्सी की तिलमिलाहट के कारण वे परेशान हैं और अभी उनको और बहुत दिनों तक विपक्ष में ही रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस की दोहरी नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां वे चुनाव जीतते हैं, वहां ईवीएम सही है और जहां चुनाव हारते हैं, वहां ईवीएम खराब है। उन्होंने संवैधानिक एवं स्वतंत्र संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाने की कांग्रेस की प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस ने सेना पर आरोप लगाए। अब चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, न्यायालय पर आरोप लगाते हैं। ऐसी कौन-सी संस्था है, जिस पर इन्होंने आरोप नहीं लगाया है। मुख्यमंत्री ने देश की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक स्थलों को लेकर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने देश की संस्कृति पर हमेशा उंगली उठाई है। देश की महान संस्कृति, परंपराओं और महापुरुषों का सम्मान सर्वोपरि है। कांग्रेस को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमारे महापुरुषों के सम्मान के बारे में इनको सोचना चाहिए और जब तक ये ऐसा नहीं सोचेंगे, कांग्रेस की दुर्गति और ज्यादा होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हवाई किराये में बढ़ोतरी की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

संचार जगत



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के दौरान घरेलू हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी को लेकर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर टिकट की कीमतें बहुत ज्यादा हैं तो यात्री हवाई यात्रा न करें। यह आवेदन जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और अपारेश कुमार सिंह की बेंच के सामने मेंशन किया गया था, जहां आवेदक के वकील ने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान हवाई किराये में 700 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। वकील ने दलील दी कि हवाई यात्रा एक आवश्यक सेवा बन गई है और इस तरह की भारी बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

हालांकि, जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने तत्काल लिस्टिंग की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि हवाई यात्रा न करें। यह अंतरिम आवेदन एक लंबित पीआईएल में दायर किया गया है, जिसमें नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कथित अपारदर्शी, शोषणकारी और एल्गोरिदम-आधारित मूल्य निर्धारण प्रथाओं को चुनौती दी गई है, जिसमें अप्रत्याशित किराया उतार-चढ़ाव, अंतिम समय में भारी बढ़ोतरी और एयरलाइंस द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क शामिल हैं।

शरद पवार की हालत स्थिर, आज अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी



संचार जगत

पुणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की हालत स्थिर है और वे ठीक हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें संभवतः आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। रूबी हॉल क्लिनिक के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट, चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. परवेज के. ग्रांट ने बताया कि डॉक्टरों की टीम शरद पवार का इलाज कर रही है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच कर रही है। उनकी हालत स्थिर है और दर्द कम हो गया है। वे ठीक हैं और संभवतः आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। लगातार खांसी आने के बाद छाती में दर्द की शिकायत पर सोमवार को पवार को पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

नेपाल हेलीकॉप्टर हादसे में तमिलनाडु के वसंत कुमार की मौत



संचार जगत

काठमांडू। नेपाल में मंगलवार सुबह लैंडिंग के दौरान दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। इस हादसे में मारे गए विदेशी नागरिक की पहचान एक भारतीय के रूप में हुई है। पूर्वी नेपाल के पहाड़ी सोलुखुम्बु जिले में दो हेलीकॉप्टरों के आपस में टकरा जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया था। सोलुखुम्बु जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख, पुलिस उपाधीक्षक नवीन राजा बुढाथोकी ने बताया कि इस हादसे में तमिलनाडु के रहने वाले एक भारतीय नागरिक, वसंत कुमार की मौत हो गई। घायल व्यक्ति न्यूजीलैंड का नागरिक हैं और वो भारतीय मूल का हैं। फेरिचे में उतरते समय ये दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे।

मिलावटखोरों पर हुआ एक्शन

सीएम रेखा गुप्ता ने फेंका नकली मावा

संचार जगत



नई दिल्ली। दिवाली से पहले मिठाइयों में मिलावट करने वालों पर दिल्ली में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस बार खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिलावटी मावे के खिलाफ मैदान में नजर आईं। एक वीडियो में मुख्यमंत्री जब्त किए गए मावे को अपने हाथों से कूड़े में फेंकती दिखाई दे रही हैं। दरअसल दिवाली के त्योहार को देखते हुए दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में संदिग्ध मावा और पनीर बरामद किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, पिछले एक महीने में चार हजार एक सौ किलो से ज्यादा संदिग्ध खोया और पनीर नष्ट किया जा चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का जायजा लिया और असुरक्षित पाए गए मावे को नष्ट करवाया। खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं, ताकि मिलावट की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

दिल्ली पुलिस के एसीपी को किया निलंबित

कर्मियों के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप

संचार जगत



नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त मनस्वी वशिष्ठ को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने दो अधिकारियों के तबादले को लेकर पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिसकर्मियों द्वारा किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। यह निलंबन एक विरोध-प्रदर्शन से जुड़े विवाद के बीच हुआ है। इस प्रदर्शन के दौरान, कई पुलिसकर्मी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने दो अधिकारियों के खिलाफ जारी किए गए तबादले के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। इस घटना में शामिल होने के कारण एसीपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस बीच, एसीपी के निलंबन की खबर आने के बाद, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना विरोध-प्रदर्शन वापस लेने और न्यायिक कार्यों से दूर रहने के अपने फैसले को रद्द करने का निर्णय लिया है।

इंडिया हेल्थ लाइन की जिला कार्यकारिणी घोषित

संचार जगत



भीलवाड़ा। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की इंडिया हेल्थ लाइन की जिला कार्यकारिणी के गठन एवं घोषणा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के हिंदू हेल्थ लाइन प्रदेश महामंत्री और जिला अध्यक्ष गोपाल साहू, जिला महामंत्री रामदेव बैरवा एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष रितेश गुर्जर के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, समाजसेवा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने के विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान इंडिया हेल्थ लाइन की नवीन जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई जिसमें त्रिलोक वर्मा को इंडिया हेल्थ लाइन इकाई का भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष बनाया गया तथा कार्यकारिणी में हेमंत सिंह जिला महामंत्री,अनिल पारीक - जिला मंत्री, सुरेश कुमार योगी जिला उपाध्यक्ष, देवेश त्यागी जिला उपाध्यक्ष तथा पूरणमल को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया । राम लक्ष्मण तेली को राष्ट्रीय व्यापार परिषद् का जिला महामंत्री बनाया । पदाधिकारी ने विश्वास व्यक्त किया है कि नई कार्यकारिणी के गठन से इंडिया हेल्थ लाइन के कार्यों को नई गति मिलेगी और समाज के जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी।

जलदाय विभाग ने आयोजित की जागरूकता गतिविधियां

संचार जगत

दौसा। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और आमजन में सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। इस दौरान जलदाय विभाग की ओर से पेयजल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन पर चर्चा की गई, वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से गेटोलाव तालाब एवं रेहड़िया बांध पर कार्यक्रम आयोजित कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। जलदाय विभाग की ओर से अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पेयजल के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, संरक्षण एवं संवर्धन पर चर्चा की गई। अधिशासी अभियंता एवं तकनीकी सहायक अंकित कुमार जैन ने बताया कि एक से 7 नवम्बर तक ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत मिशन लाइफ से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रतिदिन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम में फील्ड में किए गए जल संरक्षण कार्यों के अनुभव साझा किए गए। इससे पूर्व उपस्थित कार्मिकों को पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं सतत जीवनशैली अपनाने की शपथ दिलाई गई।

रंगोली सजाकर दिया सुरक्षित दीपावली का संदेश



संचार जगत

टोंक। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठी नातमाम में दीपावली का पर्व उल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने पक्के और आकर्षक रंगों से मनमोहक रंगोलियां सजाकर पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सुरक्षित दीपोत्सव का संदेश दिया। विद्यालय में आयोजित दीपोत्सव के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। दीपोत्सव के उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर कक्षाओं, बरामदों तथा पूरे विद्यालय परिसर की सघन साफ-सफाई की। छात्राओं ने विद्यालय प्रांगण में सुंदर रंगोलियां उकेरीं।

एमआर ट्रेवल पर घी के स्टॉक की जांच

संचार जगत

जोधपुर। शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। एमआर ट्रेवल पर रखे घी के डिब्बों की जांच की गई। मौके से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने घी के सैंपल लिए। जानकारी के अनुसार, संबंधित घी का माल बाहर से आया हुआ बताया जा रहा है। घी में मिलावट की आशंका को लेकर जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार, मौके पर घी की 1690 लीटर मात्रा और 4 लाख 77 हजार 650 रुपये की बिलिंग का विवरण सामने आया है। इस हिसाब से घी की कीमत करीब 282 रुपये प्रति लीटर बताई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में आए घी की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने के बाद सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी संबंधित घी के सैंपल जांच में फेल हो चुके हैं। ऐसे में इस बार लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घी की गुणवत्ता और उसमें मिलावट की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।



अखिलेश ने कहा भाजपा के जाने पर ही बनारस मुस्कुराएगा

संचार जगत



वाराणसी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी पहुंचकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि काशी की जनता ने विधान परिषद चुनाव में भाजपा को दोहरी हार का संदेश दिया है। जो लोग डबल इंजन और डबल रफ्तार विकास की बात करते थे, उन्हें बनारस में जनता ने डबल हार और डबल जीरो दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के जाने पर ही बनारस मुस्कुराएगा। उन्होंने वादा किया कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वाराणसी में मेट्रो का निर्माण कराया जाएगा। एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद पहली बार काशी पहुंचे अखिलेश यादव का लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में पार्टी के नेताओं आशुतोष सिन्हा और लाल बिहारी यादव की जीत ने भाजपा के दावों की हकीकत सामने ला दी है। जनता ने भाजपा को नकारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वाराणसी में मेट्रो लाकर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। इसके बाद अखिलेश यादव डाफी स्थित सपा नेता रहे दिवंगत राजेश यादव नत्थू के आवास पहुंचे। वहां उन्होंने राजेश यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी चंदा यादव सहित परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की।

भाजपा अध्यक्ष दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे यूपी

गोरखपुर में करेंगे लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा



संचार जगत

गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर उत्तर प्रदेश जाएंगे। नितिन नवीन आज और कल गोरखपुर में रहेंगे। यह दौरा आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यह उनका महत्वपूर्ण सांगठनिक प्रवास होगा। इस दौरान वे पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। बाबा गोरखनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें कर आगामी अभियानों को नई दिशा देंगे। वे गोरखपुर में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। यह पदयात्रा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से शुरू होकर सरदार पटेल प्रतिमा के समीप स्थित माता काली मंदिर पर समाप्त होगी। पदयात्रा के बाद वे समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद पार्टी के जन-प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक होगी। वे उत्तर प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें प्रदेश की चुनावी रणनीति और संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

तुर्की से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया इंटरनेशनल ड्रग माफिया

संचार जगत

अहमदाबाद। गुजरात एटीएस ने इंटरनेशनल ड्रग माफिया सलीम इस्माइल डोला को गिरफ्तार कर लिया है। उसे तुर्की से डिपोर्ट करके एजेंसी के जरिए अहमदाबाद लाया गया है। सलीम डोला वडोदरा के सिंधरोट में एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था, जहां से 87.728 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की गई थी। सलीम डोला एटीएम में चल रहे एक केस में वॉन्टेड था। आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इससे पहले, इस केस में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी पर देशभर में पहले भी 8 नारकोटिक्स मामले दर्ज हैं। भारत की विभिन्न एजेंसियों की मदद से उसको तुर्की में ट्रेस किया गया और वहां से तुर्की सरकार की ओर से यहां डिपोर्ट किया गया। सिंधरोट के केस में सलीम डोला केमिकल प्रोवाइड करता था और केमिकल प्रोवाइड करने के बाद जो माल मैन्युफैक्चरिंग होता था,



उसकी बिक्री भी वही करता था और सारा माल वही ले जाता था।

चीन ने सुरंग निर्माण मशीनें रोकीं तो भारत खुद बनाएगा: पीयूष गोयल



संचार जगत

नई दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यदि चीन भारत को टनल-बोरिंग मशीन की आपूर्ति रोक देता है, तो भारत स्वयं इस तकनीक का विकास करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपने रणनीतिक हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में आयोजित यंग लीडर्स डिस्कोर्स फोरम में गोयल ने कहा कि भारत किसी भी महत्वपूर्ण तकनीक तक पहुंच के लिए दूसरे देशों से रियायतें मांगने या अपने हितों से समझौता करने वाला देश नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वे हमें टनल-बोरिंग मशीन नहीं देंगे, तो हम उसे भारत में ही विकसित कर लेंगे। भारत ऐसा देश नहीं है जो दबाव में झुक जाए। गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत के विकास की राह में आने वाली कोई भी बाधा देश की प्रगति को रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति की यात्रा में चाहे जितनी भी दीवारें खड़ी की जाएं, हम हर बेड़ी को तोड़ सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों के साथ देश के आर्थिक विकास, उभरते अवसरों और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा की।

शतरंज में खिलाड़ियों ने दिखाया जलवा

संचार जगत

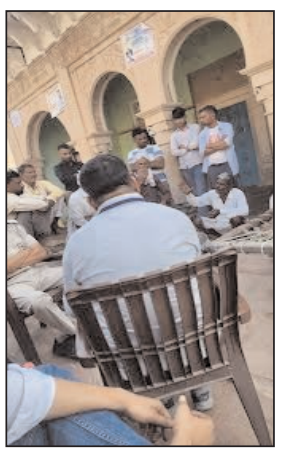


दौसा। जयपुर दिवाली सीनियर रैपिड ओपन शतरंज टूर्नामेंट में दौसा के खिलाड़ियों ने विभिन्न श्रेणियों में अपनी श्रेष्ठता साबित की। अभिवादन ने उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए टूर्नामेंट का मुख्य खिताब जीता। उन्होंने ट्रॉफी के साथ पांच हजार रुपए की नकद राशि हासिल की। उन्होंने पांचवें राउंड में जयपुर के अर्नव गुप्ता और अंतिम निर्णायक राउंड में सफेद मोहरों से खेलते हुए अनुज चौमल को शिकस्त दी। तरुण अंदाना ने शुरुआती ड्रॉ के बाद लगातार तीन जीत दर्ज कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में कनिष्का अंदाना ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि अंडर-9 बालिका वर्ग में आर्या जैमन विजेता रहीं।

ग्राम पंचायत बदलने से नाराज ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार, तहसीलदार की समझाइश भी बेअसर

संचार जगत

बयाना। बयाना के गांव नगला सिंघाड़ा में ग्राम पंचायत बदलने के विरोध में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें पुरानी ग्राम पंचायत सिंघाड़ा में ही रखा जाए या फिर उनके गांव को अलग ग्राम पंचायत बनाया जाए। मतदान बहिष्कार की सूचना पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। दरअसल, नगला सिंघाड़ा गांव पहले सिंघाड़ा ग्राम पंचायत में शामिल था, लेकिन इस बार परिसीमन के दौरान गांव को हटाकर करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित बंगसपुरा ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया। इस फैसले से नाराज ग्रामीणों ने मतदान नहीं करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पुरानी ग्राम पंचायत सिंघाड़ा में वापस शामिल किया जाए या फिर नगला सिंघाड़ा को अलग ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। वहीं, मतदान बहिष्कार की सूचना मिलने पर तहसीलदार नितेश कुमार गोयल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें मतदान के लिए



समझाया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे।

नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश



संचार जगत

जयपुर। राजस्थान में किसान आंदोलन और लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के बीच युवा नेता नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ती नजर जा रही हैं। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए बारां जिले के नयागांव स्थित उनके घर पहुंची, लेकिन नरेश मीणा घर पर नहीं मिले। इस दौरान पुलिस और उनके परिजनों के बीच काफी देर तक बहस और हंगामा भी हुआ। आखिरकार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। पिछले एक सप्ताह में नरेश मीणा के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। इनमें छबड़ा में खाद की मांग को लेकर विवाद, शिवदासपुरा टोल प्लाजा पर जाम लगाने और वनकर्मियों के साथ कथित मारपीट का मामला शामिल है। वहीं, पुलिस की कार्रवाई के बाद नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वह 6 नवंबर को शाम 5 बजे नाहरगढ़ थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।

सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत

संचार जगत

दौसा। रामसिंहपुरा गांव के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में एक ट्रक चालक की जान चली गई। गुजरात के मोरबी से टाइल्स भरकर बनास की ओर जा रहा ट्रेलर आगे चल रहे किसी अज्ञात वाहन से जा टकराया। टक्कर के तुरंत बाद शॉर्ट सर्किट से केबिन में आग लग गई। इस हादसे में टोंक जिले के टोकरवास निवासी चालक रोहित मीणा केबिन में ही फंस गया और बाहर निकलने का अवसर न मिलने से जिंदा जल गया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस और पेट्रोलिंग दल ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखवाया।

केदारताल ट्रैक हादसे में बंगाल के 5 ट्रैकर्स समेत 8 लोग लापता



संचार जगत

उत्तराखंड। उत्तराखंड में ट्रैकिंग के दौरान हिमस्खलन और अचानक आए हिमपात में फंसने से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के पांच ट्रैकर्स समेत एक अभियान दल के आठ सदस्य लापता हो गए हैं। बांकुरा के लापता ट्रैकर्स की पहचान तापस बाउरी, रतन घोष, रिंटू मंडल, उदय घोष और मनोज खवास के रूप में हुई है। पहले चार सालबानी गांव के निवासी हैं, जबकि मनोज उसी जिले के केशरा गांव के रहने वाले हैं। अन्य तीन लापता सदस्यों में से दो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से और एक उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हैं। बांकुरा के पांचों ट्रैकर्स 24 अक्टूबर को उत्तराखंड के लिए रवाना हुए थे और उन्हें नवंबर की शुरुआत में घर लौटना था। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने लापता ट्रैकर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है। जानकारी के मुताबिक, चार शेरपाओं और एक सहायक सहित 12 सदस्यीय अभियान दल गंगोत्री से केदारताल के लिए रवाना हुआ था।

पत्रकार संघ की बैठक में सुरक्षा को लेकर जताई चिंता



संचार जगत

रुदावल-रूपवास। कौशल रिसोर्ट में गुलशन कौशल की अध्यक्षता में पत्रकार संघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पत्रकारों के साथ कवरेज करते समय होने वाले दुर्व्यवहारों को लेकर चिंता व्यक्त की गई एवं पत्रकार सुरक्षा कानून को सख्ती के साथ लागू करने की सरकार से मांग की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर किसी पत्रकार के साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई परेशानी होती है तो संगठन के सभी साथी एकजुट होकर उसके समाधान का प्रयास करेंगे साथ ही किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करने वाले कार्मिक के खिलाफ लामबंद होकर उसका विरोध जताया जाएगा। अध्यक्ष रामकुमार उपाध्याय ने कहा कि पत्रकारों के हर सुख दुख में संगठन हमेशा साथ रहेगा।

जोधपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में 19 छात्र सस्पेंड

संचार जगत



जोधपुर। राजस्थान के बाड़मेर में हुई रैगिंग की घटना के बाद अब जोधपुर से भी इसी तरह की एक और घटना सामने आई है। जोधपुर के डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जूनियर एमबीबीएस छात्रों के साथ रैगिंग और दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के बाद एक जूनियर रेजिडेंट सहित 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। एक जूनियर रेजिडेंट समेत 5 छात्रों 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है जबकि बाकी 14 छात्रों को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन की अवधि के दौरान इन सभी छात्रों को क्लिनिकल पोस्टिंग, शैक्षणिक गतिविधियों और शैक्षिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। साथ ही, उनके कॉलेज हॉस्टल, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम में जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन पर मिली एक शिकायत के बाद की गई है। कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमिटी की जांच में आरोपी छात्रों को गंभीर दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार और जूनियर छात्रों पर अनुचित दबाव डालने का दोषी पाया गया। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस ने सस्पेंशन के आदेश जारी कर दिए। यह विवाद 28 अक्टूबर को कॉलेज परिसर में आयोजित क्लीन कैंपस ड्राइव के दौरान शुरू हुआ था। इससे पहले, राजस्थान के बाड़मेर स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने 80 छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी।

मतदान प्रति दिखा उत्साह

दौसा। दौसा जिले में हो रहे पंचायतीराज चुनाव के तहत 8 पंचायत समितियों में मतदान हुआ। चुनाव के तीसरे चरण के तहत सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिलीं। लालसोट, लवाण, नांगल राजावतान, रामगढ़ पचवारा, शिवसिंहपुरा, दौसा, सिकंदरा और सिकराय पंचायत समिति क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से वोट डाले गए। जिला परिषद के 24 और पंचायत समिति के 142 वार्डों के लिए 6 लाख 55 हजार 698 मतदाताओं के मताधिकार प्रयोग के लिए सुरक्षा के इंतजाम रहे। सिकंदरा पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम निहालपुरा स्थित बूथ संख्या 62 पर ईवीएम में खराबी आ गई, जिसके कारण पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतदान करीब आधे घंटे तक बाधित रहा।

ट्रैवल एजेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, नई लैंड पूलिंग पॉलिसी मंजूर

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में कुल 7 एजेंडे रखे गए थे। सभी एजेंडों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। विदेश भेजने के नाम पर युवाओं से ठगी रोकने के लिए ट्रैवल एजेंटों का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने, नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 लागू करने और अधिसूचित ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई।

ट्रैवल एजेंट्स ब्योरा डिजिटल होगा

अवैध तौर पर युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले ट्रैवल एजेंट्स पर शिकंजा कसने का फैसला भी लिया गया। प्रदेश में ट्रैवल एजेंटों के का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है, साथ ही जितने भी दफ्तर खोले जाएंगे सभी का अलग अलग पंजीकरण कराना जरूरी होगा। उनका सारा ब्योरा भी डिजिटल किया जाएगा ताकि आम नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर संबंधित एजेंट के पंजीकरण की प्रामाणिकता जान सकेंगे।

संशोधित लाइसेंस नवीनीकरण प्रावधान

बैठक में नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी)-2022 के खंड 9.2 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत परियोजनाओं के पूरा होने और लाइसेंस के नवीनीकरण से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार, परियोजनाओं को पांच वर्षों के भीतर पूरा करना होगा। यदि कोई परियोजना इस अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो उसके लाइसेंस का नवीनीकरण, लागू लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के भुगतान पर हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 के नियम 13 के अनुसार किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर मुहर



26 को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया

- सीएम सैनी की अध्यक्षता में कुल 7 एजेंडे रखे
- एक दिन के विशेष सत्र में संविधान के महत्व और मूल्यों पर विधानसभा में होगी चर्चा
- 629 गोशालाओं के लिए 86.95 करोड़ दिए

हरियाणा लोक सेवा आयोग विनियम 2002 में संशोधन को स्वीकृति

हरियाणा लोक सेवा आयोग (राज्य सेवा समूह-ग) विनियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इन संशोधनों का उद्देश्य आयोग में नवसृजित ग्रुप-सी पदों को शामिल करना और मौजूदा प्रावधानों को नवीनतम सरकारी नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप बनाना है।

कॉलेज कैडर ग्रुप-सी सेवा नियमों में संशोधन

बैठक में हरियाणा शैक्षणिक कॉलेज कैडर (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने के साथ-साथ सेवा संबंधी अन्य प्रावधानों को भी अद्यतन किया गया है।

टीडीआर पॉलिसी में संशोधन

मंत्रिमंडल की बैठक में हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रदान करने और उसके उपयोग से संबंधित 16 नवंबर, 2021 की नीति में संशोधनों को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य टीडीआर प्रमाण-पत्रों के मूल्यांकन, हस्तांतरण और उपयोग से जुड़े मुद्दों का समाधान करना तथा प्रदेशभर में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाना है।

भू-मालिकों को मिलेगा विकसित क्षेत्र का 50 फीसदी हिस्सा

बैठक में लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति मौजूदा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 का स्थान लेगी। नई नीति का उद्देश्य विकास परियोजनाओं में भू-मालिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। नई नीति के तहत, भू-मालिकों को स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत हिस्सा विकास एजेंसी के पास रहेगा। भू-मालिकों के हिस्से का निर्धारण बाजार मूल्य से जोड़ने संबंधी पहले के प्रावधानों को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार गौशालाओं के विकास और गौवंश संरक्षण की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी कड़ी में गत दिवस प्रदेश की 629 गोशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख की राशि प्रदान की गई है।

नीट पीजी में रैंक को मिलेगा अधिक महत्व

नई दिल्ली। मेडिकल पीजी में दाखिले की प्रक्रिया 2027 से बदल सकती है। समिति की



रिपोर्ट के बाद रैंक आधारित दाखिला व्यवस्था को अधिक महत्व देने की चर्चा तेज हो गई है। क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में भारी कटौती के विवाद के बाद केंद्र की विशेषज्ञ समिति ने समीक्षा की है। बदलाव लागू होने पर काउंसलिंग की पात्रता और खाली सीटें भरने के नियम बदल सकते हैं।

खबर संक्षेप



चेक ओपन : सेंथिलकुमार ने जीता खिताब

नई दिल्ली। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी वेलवन सेंथिलकुमार ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ब्रनो में खेले गए 35,000 अमेरिकी डॉलर इनामी चेक ओपन का खिताब जीता। इस 28 वर्षीय खिलाड़ी ने फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व रैंकिंग में 31वें स्थान पर काबिज स्कॉटलैंड के ग्रेग लोब्बन को चार गेम तक चले मैच में हराया। विश्व में 42वें नंबर के खिलाड़ी और यहां चौथी वरीयता प्राप्त सेंथिलकुमार ने लोब्बन को 13-11, 11-5, 8-11, 11-7 से पराजित करके अपना 12वां पीएसए टूर खिताब जीता। यह उनका दूसरा कॉपर-स्तरीय खिताब है। इससे पहले उन्होंने अगस्त में बुडापेस्ट ओपन के रूप में अपना पहला कॉपर-स्तरीय खिताब जीता था।

विश्व चैंपियनशिपः भारतीय टीम ने जीता स्वर्ण पदक



दोहा। भारत के रविंदर सिंह, सौरभ चौधरी और अमनप्रीत सिंह की तिकड़ी ने आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रविंदर ने इस स्पर्धा का व्यक्तिगत रजत पदक भी अपने नाम किया। यह स्पर्धा ओलंपिक प्रतियोगिताओं की सूची में शामिल नहीं है। रविंदर भारत के सबसे अधिक अंक हासिल करने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने कुल 559 अंक प्राप्त किए। कई बार विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत चुके सौरभ ने 551 अंक हासिल किए जबकि अमनप्रीत सिंह ने 549 अंक बनाए। इस तरह भारतीय टीम ने कुल 1659 अंक हासिल किए। चीन के झांग बिंगचेन, ल्यू जुनयी और फेंग लिनलांग ने कुल 1648 अंक हासिल कर रजत पदक जीता।

एक साल के लिए स्थगित एशियाई कप



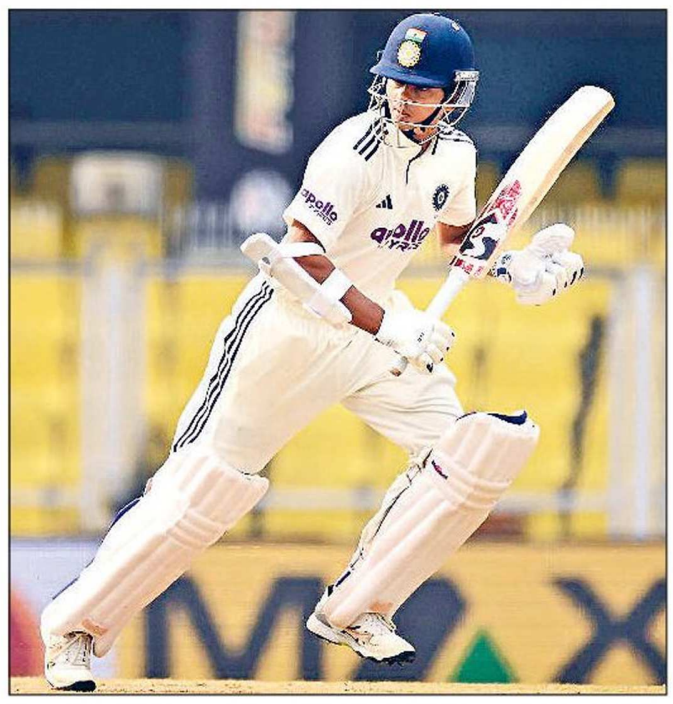
कुआलालंपुर। एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और मेजबान सऊदी अरब में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण 2027 में होने वाले एशियाई कप को लगभग एक साल के लिए स्थगित कर दिया है। एएफसी ने कहा कि सऊदी अरब के आयोजकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद उन्होंने इस टूर्नामेंट को स्थगित करने का फैसला किया। पहले यह टूर्नामेंट अगले साल सात जनवरी से शुरू होना था लेकिन अब यह 23 दिसंबर 2027 से खेला जाएगा। एएफसी ने 23 दिसंबर 2027 से 21 जनवरी 2028 तक इस टूर्नामेंट को आयोजित करने का फैसला किया है लेकिन इसे अभी विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा से मंजूरी मिलनी बाकी है।

नाबाद 155 रन की पारी से फॉर्म में लौटे यशस्वी

जायसवाल और राठौड़ की शतकीय पारी न्यूजीलैंड ए के खिलाफ टेस्ट रहा ड्रॉ

नई दिल्ली/संचार जगत

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच मंगलवार को ड्रॉ समाप्त हुए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट क्रिकेट मैच में शतक जड़कर दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला से पहले अपनी फॉर्म को लेकर भारतीय टीम प्रबंधन को आश्वस्त किया। जायसवाल ने मैच के चौथे और अंतिम दिन न्यूजीलैंड ए के आक्रमण की जमकर धुनाई करते हुए केवल 162 गेंदों में नाबाद 155 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज यश राठौड़ ने भी नाबाद 100 रन बनाए, जिससे भारत ए ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 282 रन बनाए। इसके बाद दोनों कप्तान ने मैच ड्रॉ करने पर सहमति जताई। राठौड़ के शतक पूरा करने के तुरंत बाद मैच ड्रॉ समाप्त घोषित कर दिया गया। राठौड़ और जायसवाल ने तीसरे विकेट के लिए 247 रन की अटूट साझेदारी की। राठौड़ ने अपनी 122 गेंदों की पारी में 9 चौके लगाए। भारत ए ने अपनी पहली पारी में 346 रन जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 424 रन बनाए थे।



राठौड़ ने जारी रखी अपनी शानदार फॉर्म

गेंद की उछाल एक समान होने के कारण शॉट लगाना आसान हो गया था। जायसवाल ने स्लॉग स्वीप शॉट से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना 17वां शतक पूरा किया। इसके बाद वह अधिक आक्रामक हो गए और उन्होंने आगे बढ़कर कई दर्शनीय शॉट लगाए। पहले मैच में 44 और 66 रन बनाने वाले राठौड़ ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और दिखा दिया कि घरेलू क्रिकेट में उन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में क्यों गिना जाता है। उन्होंने चाय के विश्राम के बाद विदेशी धरती पर अपना पहला शतक पूरा किया।

आकर्षण का केंद्र रहे जायसवाल

हैगली ओवल की पिच काफी हद तक सपाट हो गई थी, जिससे बल्लेबाजों के लिए अपने शॉट खेलना बहुत आसान हो गया था। इसका अंदाजा भारत ए के दूसरी पारी में 5.35 के रन-रेट से रन बनाने से लगाया जा सकता है। मैच के अंतिम दिन लगभग 44 ओवर का खेल हुआ और इस बीच जायसवाल आकर्षण का केंद्र रहे। जायसवाल इस पारी से पहले रन बनाने के लिए जूझ रहे थे, जो निश्चित तौर पर मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला से पहले चिंता का विषय रही होगी। जायसवाल ने इससे पहले तीन पारियों में 17, पांच और शून्य रन बनाए थे। न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम में शामिल होने से पहले उन्होंने चंडीगढ़ के खिलाफ एकमात्र रणजी ट्रॉफी मैच खेला था, जिसमें वह खाता भी नहीं खोल पाए थे।

मैंने सिर्फ अनुशासन पर ध्यान दिया : जायसवाल

यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ शतक बनाकर फॉर्म में वापसी करने के बाद कहा कि उन्होंने इस दौरान अपनी 'प्रक्रिया, दिनचर्या और अनुशासन' पर ध्यान केंद्रित किया। जायसवाल ने ड्रॉ समाप्त हुई दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच की दूसरी पारी में नाबाद 155 रन बनाए। उन्होंने कहा कि यहां की ठंड ने उनके लिए अलग तरह की चुनौती पेश की। जायसवाल ने कहा, 'यहां बहुत ठंड है। गेंद शुरुआत में बहुत घूमती है और सीम मूवमेंट भी बहुत होता है। अच्छे गेंदबाज लगातार सही जगह पर गेंद को पिच कराते हैं। इसलिए हमें रन बनाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है।' उन्होंने कहा, 'जब विकेट बेहतर हो जाता है या गेंद पुरानी हो जाती है तो रन बनाना आसान हो जाता है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह आसान है, लेकिन आप अच्छे शॉट खेल सकते हैं। इसलिए बहुत मजा आया और यहां खेलना अच्छा लगता है। यह एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव है।'

भारतीय पुरुष टीम को 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक

विश्व चैंपियनशिप : महिला टीम ने रजत जीता

नई दिल्ली/संचार जगत

भारत ने मंगलवार को यहां चल रही आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक और महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। भारत के रविंदर सिंह, सौरभ चौधरी और अमनप्रीत सिंह की तिकड़ी ने कुल 1659 अंक से पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद इलावेनिल वलारिवान, सोनम उत्तम मास्कर और शांभवी श्रवण क्षीरसागर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में 1894.4 अंक से दूसरा स्थान हासिल किया। भारतीय टीम चीन (1899.8 अंक) से पीछे दूसरे स्थान पर रही जबकि जापान (1892.6 अंक) से कांस्य पदक जीता। इलावेनिल 634.2 अंक से भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ रहीं जबकि सोनम ने 630.2 अंक और शांभवी ने 629.7 अंक जुटाए। इलावेनिल ने क्वालीफिकेशन दौर में तीसरा स्थान हासिल कर व्यक्तिगत फाइनल में जगह बना ली थी और उनके पास पदक जीतकर भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल करने का मौका था। लेकिन वह 167.3 अंक के स्कोर से छठे स्थान पर रहकर यह मौका चूक गईं। इससे पहले रविंदर ने इस स्पर्धा का व्यक्तिगत रजत पदक भी अपने नाम किया। यह स्पर्धा ओलंपिक प्रतियोगिताओं की सूची में शामिल नहीं है। रविंदर भारत के सबसे अधिक अंक हासिल करने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने कुल 559 अंक प्राप्त किए। कई बार विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत चुके सौरभ ने 551 अंक हासिल किए जबकि अमनप्रीत सिंह ने 549 अंक बनाए। इस तरह भारतीय टीम ने कुल 1659 अंक हासिल किए। चीन के झांग बिंगचेन, ल्यू जुनयी और फेंग लिनलांग ने कुल 1648 अंक हासिल कर रजत पदक जीता। वहीं दक्षिण कोरिया की होंग सुह्योन, चोए बोरम और सो सेउंग सेओब की टीम ने 1643 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। व्यक्तिगत स्पर्धा में रूस के एंटोन अरिस्तारखोव ने 561 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। रोमानिया के लुका जोल्डिया ने 558 अंकों के साथ कांस्य हासिल किया।

आईसीसी रैंकिंग : वैष्णवी ने लगाई 53 पायदान की छलांग



दुबई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने आईसीसी विमेंस वनडे रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मुकाबलों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद वैष्णवी बॉलिंग रैंकिंग में 53 स्थान ऊपर चढ़कर 94वें नंबर पर पहुंच गई हैं। 20 वर्षीय स्पिनर ने तीसरे और आखिरी वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस दौरान अपने करियर में पहली बार पारी में 5 विकेट हासिल किए, जिससे वह भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा फायदा पाने वाली खिलाड़ी बन गईं।

महिला टी-20

प्रेमा ने बनाया रिकॉर्ड, 14 गेंदों मे जड़ा अर्धशतक



नई दिल्ली/संचार जगत

भारतीय ऑलराउंडर प्रेमा रावत ने सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी के मैच में मंगलवार को 14 गेंदों में अर्धशतक जड़कर महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया।

उत्तराखंड की इस 24 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी पारी में छह चौके और चार छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 357 रहा। उनकी इस पारी के दम पर उत्तराखंड ने हैदराबाद को 89 रन से हराया। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के नाम है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। इंग्लैंड की मैरी केली और ऑस्ट्रेलिया की लौरा हैरिस ने भी घरेलू क्रिकेट में 15 गेंदों में अर्धशतक बनाए हैं।

गेंदबाजी में प्रेमा का जलवा

रावत की नाबाद 50 रन की विस्फोटक पारी की बदौलत उत्तराखंड ने निर्धारित 20 ओवरों में दो विकेट पर 187 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम 8 विकेट पर 98 रन ही बना सकी। प्रेमा रावत ने गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट लिए।

मैक्सवेल ने 14 साल के अंतरराष्ट्रीय कॅरियर को कहा अलविदा

नई दिल्ली/संचार जगत



ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिससे उनके 14 साल के करियर का अंत हो गया है। सी मि त ओवरों की क्रिकेट के इस 38 वर्षीय धुरंधर खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपना आखिरी मैच इस साल की शुरुआत में आईसीसी टी20 विश्व कप के दौरान ओमान के खिलाफ खेला था। मैक्सवेल ने कहा, 'मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ-साथ विक्टोरिया के लिए घरेलू क्रिकेट (50 ओवर के मैच और लाल गेंद से खेले जाने वाले चार दिवसीय क्रिकेट) से भी संन्यास ले रहा हूं।' उन्होंने कहा, 'ओलंपिक खेलों (2028 में) को देखते हुए मुझे लगता है कि अगले 12 से 24 महीनों में काफी बदलाव होने वाले हैं, ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि युवा खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के दबाव का सामना करने का मौका मिले।'

कनकशन के कारण कॉनवे पहले वनडे से बाहर, सीफर्ट टीम में शामिल

नई दिल्ली/संचार जगत

न्यूजीलैंड के सीनियर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे अभ्यास सत्र के दौरान साथी खिलाड़ी मैट हेनरी से टकराने से सिर में चोट लगने (कनकशन) के कारण भारत के खिलाफ बुधवार को होने वाले पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने मंगलवार को बताया कि टिम सीफर्ट उनकी जगह लेंगे।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पुष्टि की कि कॉनवे को जांच के लिए अस्पताल ले जाने के बाद 'कनकशन' का पता चला, जिसके कारण वह श्रृंखला के पहले मैच में



नहीं खेल पाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बयान में कहा, 'कॉनवे को जांच के लिए अस्पताल के दुर्घटना एवं आपातकालीन विभाग (ए एंड ई) में ले जाया गया, जहां 'कलकशन' की पुष्टि हुई। इस कारण वह कल भारत के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेल पाएंगे।''

यह टक्कर तब हुई जब दोनों खिलाड़ी श्रृंखला के पहले मैच से पूर्व ऑकलैंड के ईडन पार्क में टीम के अभ्यास सत्र के दौरान हवा में लहराते कैच को लेने की कोशिश कर रहे थे। सैंटनर ने पुष्टि की कि हेनरी ठीक हैं। उन्होंने मैच की कहा, 'मुझे लगता है मैट को सिर में चोट लगी थी। वह ठीक लग रहा है, लेकिन डेव (कॉनवे) को तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया है। वास्तव में वह टक्कर अच्छी नहीं लग रही थी।'

एथलीट सुधा सिंह हटीं चुनावी दौड़ से

आईओए एथलीट आयोग की निर्विरोध सदस्य चुनी गईं सिंधू-मीराबाई

नई दिल्ली/संचार जगत

ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू और मीराबाई चानू सहित 10 खिलाड़ियों को मंगलवार को निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के एथलीट आयोग का सदस्य चुन लिया गया। पूर्व ट्रैक एवं फील्ड एथलीट सुधा सिंह के चुनावी दौड़ से हटने के बाद मतदान कराने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 10 सीट के लिए केवल 10 उम्मीदवार ही रह गए थे।

निर्वाचन अधिकारी संजय के श्रीवास्तव ने 5 पुरुष और 5 महिला सहित सभी 10 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। इससे पहले बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी।



आईओए एथलीट आयोग के निर्विरोध निर्वाचित सदस्य

पीवी सिंधू, मीराबाई चानू, हरमनप्रीत सिंह, सलीमा टेटे, स्वप्निल कुसाले, भवानी देवी, तजिंदरपाल सिंह तूर, बोम्बाल्या देवी, साजन प्रकाश और मंजीत सिंह।

आईएसएसएफ एथलीट समिति का चुनाव लड़ेगी मनु भाकर

दो ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर 2026-2030 के लिए अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) एथलीट समिति का चुनाव लड़ेंगी, जिन्हें पिस्टल वर्ग में नामित किया गया है। भाकर उन दस उम्मीदवारों में से हैं, जो पिस्टल श्रेणी में दो पदों के लिए दौड़ में होंगे। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा को बचाना और ओलंपिक कार्यक्रम में इसके दीर्घकालिक भविष्य को सुरक्षित करने के साथ आईएसएसएफ विश्व कप में बेहतर इनामी राशि के लिए जोर देना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। भाकर ने कहा, 'शीर्ष स्तर पर खेलने के बाद मुझे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के सामने आने वाली चुनौतियों और मौकों दोनों का अनुभव है। मेरा मानना है कि खिलाड़ियों को खेलों में भागीदारी के अलावा भविष्य को गढने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।'

इस वर्ष धनतेरस पर 46 से 52 टन सोना बिकने की उम्मीद

- चांदी की बिक्री केवल धनतेरस पर 250 टन के करीब होने की संभावना
- आभूषणों की वैश्विक मांग 17 फीसदी गिरकर 313 टन रही
- सिक्कों की खरीदी में भी कमजोरी दर्ज की गई

नई दिल्ली/संचार जगत

धनतेरस और दिवाली से पहले सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। त्योहारों सीजन से ठीक पहले यह कीमतों यह गिरावट ग्राहकों के लिए खरीदारी का अवसर तो है साथ ही सर्राफा बाजार के लिए यह राहत की बात है, क्योंकि त्योहारों से पहले कीमतें गिरने से बिक्री बढ़ने की उम्मीद ज्वेलर्स की बढ़ गई हैं।

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) का कहना है, पिछले साल धनतेरस पर 36 टन सोना बिका था जिसकी तुलना में इस साल धनतेरस पर 46 से 52 टन सोना बिकने की उम्मीद है, वहीं चांदी की



बिक्री केवल धनतेरस पर 250 टन के करीब होने की संभावना है।त्योहारों से पहले सोने और चांदी कीमतों में आई गिरावट सर्राफा कारोबारियों और ग्राहकों दोनों के लिए सकारात्मक है। इस साल धनतेरस और दिवाली में सोने की मांग लगभग 7 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी और चांदी की मांग 7 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल धनतेरस पर 46 से 52 टन सोना बिकने की उम्मीद है, वहीं चांदी की बिक्री केवल धनतेरस पर 250 टन के करीब होने की संभावना है। दिवाल और धनतेरस को मिलाकर कुल 65 टन सोना बिकने का अनुमान है, जबकि कुल चांदी की बिक्री 300 टन के आसपास होने की संभावना है।

> **सोने-चांदी की कीमतों गिरावट आने की गुंजाइश बनी है, फिलहाल त्योहारों तक सोने में 3 प्रतिशत और चांदी में 7-8 प्रतिशत की गिरावट की संभावना है। वे कहते हैं, पिछले साल की तुलना में इस साल दिवाली और धनतेरस पर अच्छी बिक्री होगी।**

चांदी 2,000 रुपये लुढ़की

नई दिल्ली,आरएनएन। वैश्विक बाजारों में बिकवाली और कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के बीच निवेशकों के द्वारा सतर्क रुख अपनाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 700 रुपये टूटकर 1,41,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना सोमवार के 1,42,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद भाव से 700 रुपये टूटकर 1,41,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया। पिछले कारोबारी सत्र में स्थिर रही चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई। चांदी 2,000 रुपये टूटकर 1,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई, जबकि सोमवार को इसका भाव 1,86,000 रुपये प्रति किलोग्राम था।

ऊंची कीमतों के कारण सोने की वैश्विक मांग में गिरावट दर्ज

विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 की तीसरी तिमाही में सोने की वैश्विक मांग में एक फीसदी की कमी आई है। ऊंची कीमतों और बाजार में अनिश्चितता के कारण यह मांग 1,369 टन रह गई। हालांकि, मांग का कुल मूल्य 22 फीसदी बढ़कर 188 अरब डॉलर पहुंच गया। ऊंची कीमतों का सबसे अधिक असर आभूषणों की मांग पर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, इस तिमाही में सोने की औसत कीमत 4,262 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस रही। गोल्ड ईटीएफ और केंद्रीय बैंकों की खरीद में मजबूती देखने को मिली। व्यक्तिगत निवेशकों की ओर से सोने की छड़ और सिक्कों की खरीदारी में कमजोरी दर्ज की गई। इनकी वैश्विक मांग 19 फीसदी घटकर 268 टन रह गई। कीमतों को लेकर स्पष्ट दिशा न होने से निवेशकों ने खरीदारी से दूरी बनाए रखी। चीन और भारत में मौसमी सुधार तथा कीमतों में नरमी से तिमाही-दर-तिमाही आधार पर सोने की मांग में 12 फीसदी का सुधार हुआ। डब्ल्यूजीसी की ''तीसरी तिमाही 2026 स्वर्ण मांग रुझान'' रिपोर्ट बताती है कि ऊंची कीमतों के कारण आभूषणों की वैश्विक मांग 17 फीसदी गिरकर 313 टन हो गई। यह किसी भी तीसरी तिमाही का अब तक का सबसे कमजोर आंकड़ा है।

▶ विषय विशेषज्ञ बनाएंगे नीट-जेईई पेपर, एग्जाम से ठीक पहले होगा फाइनल

NTA का 5000 से बड़ा एक्सपर्ट पैनल तैयार

इस पैनल में शिक्षाविद, वैज्ञानिक और विशेषज्ञों को किया गया शामिल

नई दिल्ली/संचार जगत

देश के लाखों युवाओं के भविष्य और करियर से जुड़ी एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है। नीट , जेईई मेन, सीयूईटी और यूजीसी-नेट जैसी देश की सबसे बड़ी और संवेदनशील प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने अपने पूरे सिस्टम को नए सिरे से ढालना शुरू कर दिया है।

अक्सर पेपर लीक और धांधली के आरोपों से जूझने वाली एनटीए ने अब एक ऐसा फुलप्रूफ प्लान तैयार किया है, जिससे पर्चा लीक होने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। एनटीए के इस नए मास्टरप्लान की खास बातें- एनटीए ने देश भर के शीर्ष शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, अनुवादकों और विषय विशेषज्ञों का एक बहुत बड़ा पैनल तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार, 5,000 से अधिक विशेषज्ञों को विषय-वस्तु तैयार करने, प्रश्न पत्रों की जांच, अनुवाद (एआई अनुवाद की समीक्षा) और आंसर-की सत्यापन के



लिए एम्पैनल किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आवेदन की कोई अंतिम तिथि तय नहीं की गई है। एनटीए पूरे साल इस पैनल में नए-नए योग्य विशेषज्ञों को जोड़ता रहेगा ताकि प्रश्न बैंक का दायरा लगातार बढ़ता रहे। एनटीए का मुख्य उद्देश्य इतना विशाल क्वेश्चन बैंक बनाना है ताकि प्रश्न पत्र तैयार करने या अनुवाद करने वाले विशेषज्ञों को खुद यह पता न हो कि उनके द्वारा तैयार किया गया सवाल किस परीक्षा में और कब पूछा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि एनटीए ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है ताकि परीक्षा शुरू होने से महज कुछ मिनट पहले क्वेश्चन बैंक से रैंडम तरीके से सवालों का चयन करके फाइनल पेपर तैयार किया जा सके। एजेंसी एक ऐसे एग्जाम-अग्नोस्टिक मॉडल पर काम कर रही है, जिससे पूरी परीक्षा प्रणाली किसी एक खास वेंडर, तकनीक या प्लेटफॉर्म पर निर्भर न रहे।

चार -लेयर वेरिफिकेशन: कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों की नो-एंट्री

- एनटीए के पैनल में जगह पाना इतना आसान नहीं है। विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए चार स्तरीय सख्त सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
- आवेदक की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, शोध रिकॉर्ड और अनुभव की पूरी जांच की जाती है।
- सब्जेक्ट मैटर कमेटी द्वारा समीक्षा: एक विशेष समिति आवेदक के अकादमिक कद का मूल्यांकन करती है।
- यह सुनिश्चित किया जाता है कि पैनल में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से न जुड़ा हो और न ही उसने छात्रों के लिए कोई अध्ययन सामग्री या क्वेश्चन बैंक तैयार किया हो।
- चुने गए विशेषज्ञों को एम्पैनलमेंट के वक्त और हर असाइनमेंट की शुरुआत में एक बेहद कड़े गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
- चाहे ऑनलाइन मोड (सीबीटी) में होने वाले जेईई, सीयूईटी और एनईटी हों या पेन-पेपर मोड वाला एनईईटी-एनटीए का यह नया 5,000 विशेषज्ञों का पैनल और लास्ट मिनट क्वेश्चन पेपर जनरेशन वाला सिस्टम देश के करोड़ों परीक्षार्थियों के विश्वास को फिर से बहाल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है।

दीपावली से पहले बाजार में निवेशकों पर 4 लाख करोड़ की बारिश

सेंसेक्स 1,225 अंक उछला निफ्टी भी 23,800 के पार

नई दिल्ली/संचार जगत

कच्चे तेल में उबाल के बावजूद एफएमसीजी सेक्टर की रौनक और एफआईआई को एलटीसीजी पर टैक्स में राहत के प्रस्ताव पर आज भी सेंसेक्स और निफ्टी की मजबूत शुरुआत हुई।

सेंसेक्स और निफ्टी आज दिन भर मजबूत बने रहे लेकिन आखिरी 15 मिनट में इसने ऐसी छलांग लगाई कि एकाएक सेंसेक्स 76900 और निफ्टी 23800 के पार जाकर बंद हुए। लगातार चौथे कारोबारी दिन आज ये ग्रीन रहे। ब्रोडर लेवल पर भी मार्केट में रौनक रही लेकिन स्मॉलकैप स्पेस में थोड़ी कम। निफ्टी मिडकैप 100 मंगलवार को 1



प्रतिशत से अधिक मजबूत हुआ तो निफ्टी स्मॉलकैप 100 में आधे फीसदी से थोड़ी कम बढ़त रही। इस शानदार रौनक में आज ओवरऑल बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया यानी निवेशकों की दौलत में 4 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ।

सेंसेक्स के 25 शेयरों में रही तेजी

सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं जिसमें आज 25 ग्रीन जोन में बंद हुआ। आज सबसे अधिक बढ़त एचयूएल, एयरटेल और चडीएफसी बैंक में रही तो दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट पावरग्रिड, एसबीआई और एनटीपीसी में रही। बीएसई पर मंगलवार को 4606 शेयरों की ट्रेडिंग हुई। इसमें 2510 शेयर आज मजबूत हुए तो 1895 में गिरावट रही जबकि 201 में कोई बदलाव नहीं हुआ।

रिकॉर्ड | पिछले 12 महीनों में किसी भी सुरक्षा अभियान या ऑपरेशन के दौरान एक भी जवान की जान नहीं गई

47 साल में पहली बार सीआरपीएफ में एक भी मौत नहीं

नई दिल्ली/संचार जगत

देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले 12 महीनों में ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के किसी भी जवान की मौत नहीं हुई है। सुरक्षा बल के इतिहास में 47 साल बाद ऐसा हुआ है।

सीआरपीएफ के महानिदेशक (डीजी) जीपी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि सीआरपीएफ के जवान देश के अलग-अलग संवेदनशील इलाकों में लगातार बड़े स्तर पर ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जीपी सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सीआरपीएफ के इतिहास में यह एक बड़ी उपलब्धि है। 30 अक्टूबर 2025 के बाद से अब तक लगातार 12 महीने यानी एक साल बीत चुके हैं और इस दौरान



ऑपरेशन में किसी जवान की जान नहीं गई। इससे पहले जनवरी 1979 में ऐसा दौर देखने को मिला था। यानी 47 साल बाद बल ने यह रिकॉर्ड बनाया है।

ऑपरेशनल मौत का मतलब है किसी जवान की ड्यूटी के दौरान किसी सुरक्षा अभियान या ऑपरेशन में जान जाना। स्पष्ट तौर पर समझें तो पिछले एक साल में किसी भी सुरक्षा अभियान या मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के एक भी जवान की जान नहीं गई है। अधिकारियों के मुताबिक, 30 अक्टूबर 2025 तक साल 2025 में ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हुए थे।

1939 में हुई थी सीआरपीएफ की स्थापना

करीब 3.25 लाख जवानों वाला सीआरपीएफ देश में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला प्रमुख बल है। इसकी तैनाती मुख्य रूप से तीन बड़े क्षेत्रों में है। इनमें नक्सल विरोधी अभियान, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान और पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद विरोधी अभियान शामिल हैं। सीआरपीएफ की स्थापना साल 1939 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। आजादी के बाद 1949 में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 2,270 जवान और अधिकारी देश की सुरक्षा में ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं।

लांस नायक और नायक पद होंगे बहाल: देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने लांस नायक और नायक के पदों को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। लगभग तीन दशक पहले इन दोनों पदों को क्रमशः कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों में मिला दिया गया था। सीआरपीएफ में गृह मंत्रालय के आदेश के माध्यम से 1997 में खत्म किए गए लांस नायक और नायक रैंक अभी भी सेना में कार्यरत हैं।

कानून के रखवाले ही उड़ा रहे यातायात नियमों की धज्जियां, बिना हेलमेट सड़कों पर घूमते



आम जनता का चालान काटने वाले पुलिसकर्मियों पर कौन करेगा कार्रवाई? नियमों के पालन को लेकर उठे सवाल

जयपुर। शहर की सड़कों पर यातायात नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी संभालने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही नियमों की अनदेखी करते नजर आए। जयपुर में यूनिवर्सिटी के पास एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए दिखाई दिया। इस घटना ने यातायात नियमों के पालन और पुलिस की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले आम नागरिकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। कई बार ऑनलाइन चालान काटा जाता है, तो कई मामलों में वाहन चालकों को रोककर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि जब कानून का पालन करवाने वाले ही नियमों की अनदेखी करेंगे, तो आम जनता को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश कैसे दिया जाएगा अब सवाल यह है कि बिना हेलमेट नजर आए पुलिसकर्मी का चालान कौन काटेगा? क्या यातायात नियम सभी के लिए समान हैं या फिर वर्दीधारियों को इन नियमों से छूट है? जरूरत है कि आम नागरिकों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी नियमों के उल्लंघन पर समान रूप से कार्रवाई हो, ताकि कानून के प्रति जनता का भरोसा बना रहे।

जयपुर में नकली घी पैक करने वाली फैक्ट्री सीज, 35 हजार लीटर घी जब्त

संचार जगत

जयपुर। राजधानी जयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैतपुरा स्थित घी पैकिंग फैक्ट्री को सीज कर दिया। फैक्ट्री में अलग-अलग ब्रांड के नाम से घी की पैकिंग की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 35 हजार लीटर घी का स्टॉक जब्त किया है।

घी में मिलावट की आशंका के चलते नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जयपुर सीएमएचओ की टीम ने सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक जिले में अलग-अलग स्थानों पर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। इसी दौरान जैतपुरा स्थित हिमालय डेयरी प्रोडक्ट्स फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। कई ब्रांड के नाम से हो रही थी पैकिंग सीएमएचओ फर्स्ट डॉ. रवि शेखावत के अनुसार, फैक्ट्री में राजस्थान सरस, डेयरी ब्रदर्स, श्री किरण सरस, माटुला, चॉइस डेयरी, रघु श्री और गणक सहित विभिन्न ब्रांड के नाम से घी पैक किया जा रहा था। यहां 200 एमएल, 500 एमएल, एक लीटर, दो लीटर, पांच लीटर और 15 लीटर की पैकिंग टेट्रा पैक और टिन में मिली। इसके अलावा बड़े साइलो में भी पैकिंग के लिए घी रखा हुआ था। घी का फ्लेवर भी मिला, नमूने जांच के लिए भेजे निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में घी का फ्लेवर भी मिला। टीम को तैयार घी की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत हुई और उसमें मिलावट की आशंका जताई गई। इसके बाद अलग-अलग नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए।

दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित

जयपुर। देवनानी के मुख्य आतिथ्य में समर्थ भारत राजस्थान की ओर से दीपावली के अवसर पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया।

नकली दवाओं के रैकेट पर ईडी की छापेमारी

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत नकली दवाओं के रैकेट से जुड़े लोगों और कंपनी के पांच ठिकानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। ईडी की ओर से यह कार्रवाई 18 अगस्त से चल रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई। यह केस तवरेकेरे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई 18 अगस्त को एक प्रॉपर्टी पर की गई जॉइंट सर्च से जुड़ी है।

मॉस्को नहीं चाहता तनाव कम करना

दक्षिणी यूक्रेन में राहत केंद्र पर रूसी हमला, 29 लोगों की मौत, 20 लापता

नई दिल्ली/संचार जगत

दक्षिणी यूक्रेन में मानवीय सहायता केंद्र और एक आश्रय स्थल पर सोमवार को रूस की ओर से किए गए हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि अब भी करीब 20 लोग लापता हैं ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 'एक्स' पर एक संदेश में कहा कि रूसी हमले में सबसे पहले मानवीय सहायता सामग्री वितरित करने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक स्कूल की इमारत को निशाना बनाया गया और इसके बाद पास स्थित एक आश्रय स्थल पर भी हमला किया गया। यह इस बात सबूत है कि रूस तनाव



बचाव अभियान में जुटे यूक्रेनी सैनिक

कम करना नहीं चाहता। दक्षिणी जापोरिज्जिया क्षेत्र के कोमिशुवाखा गांव में ये हमले ऐसे समय हुए, जब सोमवार को देश के एक अन्य दक्षिणी क्षेत्र खेरसॉन में स्थानीय स्तर पर लागू युद्धविराम समाप्त हो गया। इस समझौते के तहत रूस के कब्जे वाले अग्रिम क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित निकालने की अनुमति दी गई थी। जेलेंस्की ने कहा कि रूस शांति का समर्थन नहीं करता है।

संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में रक्षा मंत्री बोले

आज के समय में तकनीक युद्ध का अभिन्न अंग, निजी क्षेत्र आगे आएं

नई दिल्ली/संचार जगत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज के बदलते समय में तकनीक युद्ध का अभिन्न अंग है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से नई-नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। नए हथियारों, मिसाइलों और प्रणालियों का परीक्षण हो रहा है। इसके साथ ही सरकार ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया है और उसे समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने मंगलवार को जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।

सेनाओं ने लगातार सुधार और बदलाव किए

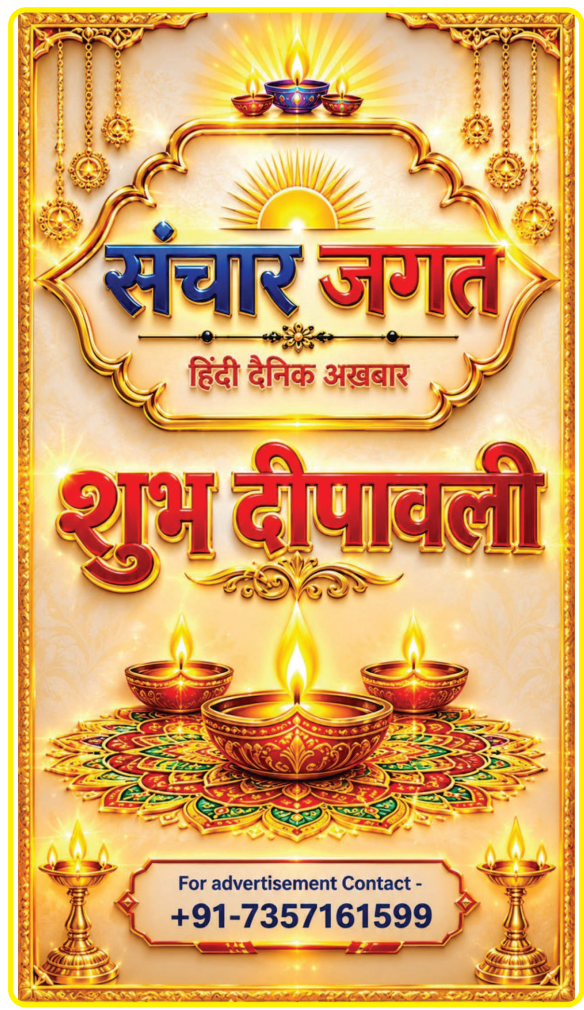


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने कहा कि तीनों सेनाओं ने अपनी संरचनाओं और सैन्य गठन में लगातार सुधार और बदलाव किए हैं। उदाहरण के तौर पर, भारतीय सेना में असनी, भैरव और शक्तिबाण प्लाटून जैसी नई सैन्य टुकड़ियां आज की परिचालन संबंधी जरूरतों और युद्ध की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप काफी उपयोगी साबित हो रही हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से लेकर बड़ी कंपनियां तक आज रक्षा क्षेत्र में योगदान दे रही हैं।

रक्षा बजट बढ़कर 7 लाख 85 हजार करोड़ रुपए किया

राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल आधुनिक उपकरण हासिल करना नहीं, बल्कि एक ऐसा रक्षा तंत्र तैयार करना है, जिसमें हमारी सेनाओं की जरूरतों के अनुरूप तकनीक का विकास हो, भारतीय उद्योग की भागीदारी बढ़े और देश की रणनीतिक निर्भरता कम हो। वित्त वर्ष 2026-27 में देश का कुल रक्षा बजट बढ़कर 7 लाख 85 हजार करोड़ रुपए हो गया है। इसमें सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण और खरीद के लिए 2 लाख 19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।



स्वामित्व, प्रकाशक एवं संपादक : अवंतिका राठौड़ - पी.के. प्रिंटर्स एंड स्टेशनर्स, 31, राम मंदिर के पास, पटेल नगर, 22 गोदाम, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। कार्यालय : जे-17, रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर। संपर्क : 0141 463 7668
ई-मेल : sancharjagat@gmail.com| आरएनआई नं. : RAJHIN/2014/55262 समाचार चयन के लिए पीआरबी अधिनियम के तहत जिम्मेदार। न्यायाधिकार क्षेत्र : जयपुर महानगर।